

मुख्यमंत्री साय का संकल्प: आदिवासी अंचलों सहित सभी नागरिकों तक पहुँचे विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सुविधा

रायपुर

छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और सुदृढीकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया। मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की उपस्थिति में चिकित्सा शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ और कॉन्टिनेंटल हॉस्पिटल तेलंगाना के बीच लाइसेंस समझौते (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। यह अनुबंध प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत किया गया है। इस अवसर पर वन एवं परिवहन मंत्री केदार कश्यप, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार पिंगुआ, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, सचिव राहुल भगत, स्वास्थ्य सचिव अमित कटारिया, आयुक्त स्वास्थ्य डॉ. प्रियंका शुक्ला, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (एनएमडीसी) के अधिकारी जयदीप दास गुप्ता एवं श्रीनिवास राव तथा कॉन्टिनेंटल हॉस्पिटल हैदराबाद के अध्यक्ष डॉ. गुरुनाथ रेड्डी, डॉ. रघुनाथ रेड्डी और के.वी. रेड्डी सहित अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य है कि आदिवासी अंचलों सहित प्रदेश के हर नागरिक तक विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएँ पहुँचे।



उन्होंने कहा कि आठ वर्ष पूर्व इस अस्पताल के निर्माण की शुरुआत की गई थी और आज जब छत्तीसगढ़ अपनी रजत जयंती मना रहा है, तब इस एमओयू का होना ऐतिहासिक महत्व रखता है। गणेश महोत्सव के पानव अवसर पर हुआ यह समझौता प्रदेशवासियों के लिए शुभ संकेत है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि बस्तर क्षेत्र के लोग लंबे समय से उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं से वंचित रहे हैं, किंतु अब यह अस्पताल उनके लिए

वरदान साबित होगा। विशेषकर नक्सल मोर्चे पर तैनात जवानों के लिए यह जीवनरक्षक सिद्ध होगा। पहले चायल जवानों को एयर एंबुलेंस से रायपुर भेजना पड़ता था, अब जगदलपुर में ही उन्हें अत्याधुनिक इलाज उपलब्ध होगा। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य है कि हर नागरिक को समय पर बेहतर स्वास्थ्य सेवाएँ मिलें। बस्तर अंचल में सुपर

स्पेशियलिटी हॉस्पिटल की स्थापना राज्य और क्षेत्रवासियों के लिए गर्व की बात है। पहले ये सेवाएँ केवल रायपुर और बिलासपुर जैसे बड़े शहरों में उपलब्ध थीं, लेकिन अब बस्तर के लोग भी इन सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए हर संभव संसाधन उपलब्ध कराएगा। स्वास्थ्य सचिव श्री अमित कटारिया ने जानकारी दी

कि इस सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल के निर्माण पर 200 करोड़ रुपये की लागत आई है, जिसमें से 120 करोड़ रुपये केंद्र सरकार और 80 करोड़ रुपये राज्य सरकार ने वहन किए हैं।

राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (एनएमडीसी) ने भी इस परियोजना में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने बताया कि यह अस्पताल 11 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है और अत्याधुनिक मशीनों एवं उपकरणों से सुसज्जित है। यह 10 मंजिला अस्पताल 240 बिस्तरों की क्षमता वाला होगा। इसमें हृदय रोग (कार्डियोलॉजी), किडनी रोग (नेफ्रोलॉजी), मस्तिष्क रोग एवं न्यूरो सर्जरी, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी जैसे विभाग संचालित होंगे। ओपीडी, आईसीयू और आपातकालीन सेवाओं सहित गहन चिकित्सा की अत्याधुनिक सुविधाएँ यहाँ उपलब्ध होंगी। विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम सरकारी दर पर उपचार प्रदान करेगी।

सरकारी दर पर उपलब्ध इन सेवाओं का लाभ न केवल बस्तर संभाग बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ और देशभर के मरीज उठा सकेंगे। इस अवसर पर उपस्थित अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और कॉन्टिनेंटल हॉस्पिटल प्रबंधन के प्रतिनिधियों ने इस ऐतिहासिक पहल को प्रदेश के स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए मौलिक कदम बताया। इससे बस्तर अंचल के लाखों लोगों को उन्नत स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलेगा और बड़े शहरों पर उनकी निर्भरता कम होगी। यह अस्पताल न केवल बस्तर बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ और देश के मरीजों के लिए नई आशा और जीवनदायी सुविधा साबित होगा।

छत्तीसगढ़ जीरो पावर कट स्टेट से अब मुफ्त बिजली की ओर: मुख्यमंत्री साय

रायपुर

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने नवा रायपुर सेक्टर-24 में छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनी के संयुक्त मुख्यालय भवन का शिलान्यास किया। रजत जयंती वर्ष और गणेशोत्सव जैसे पानव अवसर पर सम्पन्न इस समारोह में उन्होंने विधिवत पूजा-अर्चना की और भवन का श्री-डी मॉडल अनावृत किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह भवन अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्यक्षमता को नई ऊँचाई देगा, तीनों पावर कंपनियों के बीच समन्वय को मजबूत करेगा और उपभोक्ताओं को एक ही छत के नीचे सभी सेवाएँ उपलब्ध कराएगा। उन्होंने इस अवसर पर एक पेड़ का नाम अभियान के अंतर्गत मौलिकी पौधरोपण किया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ को 25 वर्षीय यात्रा यह प्रमाण है कि जब संकल्प और संवेदनशीलता साथ चलें तो परिणाम ऐतिहासिक होते हैं। वर्ष 2000 में प्रदेश केवल 1400 मेगावाट बिजली उत्पादन करता था, आज यह क्षमता बढ़कर 30 हजार मेगावाट हो गई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में 1320 मेगावाट क्षमता के नए संयंत्र का शुभारंभ इस उपलब्धि को और सुदृढ करने वाला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ की यह प्रगति हर नागरिक के विश्वास, मेहनत और भागीदारी का परिणाम है। उन्होंने कहा कि हाल ही में सम्पन्न उनकी



जापान और दक्षिण कोरिया यात्रा ने यह अनुभव कराया कि छत्तीसगढ़ अब वैश्विक स्तर की अधोसंरचना और कार्यसंस्कृति की ओर तेजी से बढ़ रहा है। संयुक्त मुख्यालय भवन इस दिशा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि भवन का निर्माण गुणवत्ता और समयबद्धता के साथ पूरा किया जाए, ताकि यह ऊर्जा क्षेत्र में छत्तीसगढ़ की नई पहचान बने। मुख्यमंत्री ने बताया

कि नई उद्योग नीति के अंतर्गत पावर सेक्टर में हाल ही में लगभग तीन लाख करोड़ रुपये के एमओयू हुए हैं। इसके परिणामस्वरूप आने वाले वर्षों में 30 हजार मेगावाट अतिरिक्त बिजली उत्पादन संभव होगा। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि न केवल प्रदेशवासियों को 24 घंटे निर्बाध बिजली उपलब्ध कराएगी बल्कि पड़ोसी राज्यों की जरूरतें भी पूरी करेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लागू पीएम

सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना ने छत्तीसगढ़ को मुफ्त बिजली की ओर तेजी से अग्रसर कर दिया है और अब दूरस्थ अंचलों तक इस योजना का लाभ पहुँच रहा है। वन मंत्री केदार कश्यप ने इस अवसर पर भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी को राज्य निर्माण में उनके योगदान के लिए नमन किया। उन्होंने कहा कि लगभग 270 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाला यह भवन ग्रीन एनर्जी आधारित होगा और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणास्रोत सिद्ध होगा।

उद्देश्यपूर्ण है कि संयुक्त मुख्यालय भवन 10,017 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में नौ मंजिला स्वरूप में निर्मित होगा। इसमें छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड और पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के लिए तीन अलग-अलग टॉवर होंगे। 1300 कर्मचारियों की क्षमता वाले इस भवन में 210 सीटों का प्रेक्षागृह, कर्मचारियों के लिए जिम, दो मंजिला बेसमेंट पार्किंग, मैकेनिकल स्टैक पार्किंग और ई-व्हीकल चार्जिंग जैसे अत्याधुनिक सुविधाएँ उपलब्ध होंगी। यह भवन बीईई की पाँच सितारा और गृह की फ्लैग स्टार ग्रीन रेटिंग मानकों के अनुरूप निर्मित होगा तथा भवन प्रबंधन प्रणाली से इसका संपूर्ण संचालन होगा। नवा रायपुर में बन रहा यह अत्याधुनिक भवन मंत्रालय, संचालनालय और पुलिस मुख्यालय के समीप होने से अंतर्विभागीय समन्वय को और सुदृढ करेगा तथा प्रदेश के ऊर्जा क्षेत्र को नई ऊँचाई प्रदान करेगा।

रामदास अटावले का छत्तीसगढ़ प्रवास, योजनाओं की प्रगति की समीक्षा



रायपुर

केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अटावले आज छत्तीसगढ़ प्रवास पर रायपुर पहुँचे। उन्होंने राज्य अतिथि गृह पहुँचा न छत्तीसगढ़ सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की। बैठक में अटावले ने विशेष रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांगजन हितेषी योजनाओं की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि योजनाओं का लाभ प्राप्त हितग्राहियों तक समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पहुँचे। इसके साथ ही उन्होंने विभागीय समन्वय को और सुदृढ बनाने तथा समाज

के वंचित वर्गों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए ठोस कदम उठाने पर जोर दिया। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार सामाजिक न्याय और समान अवसर की दिशा में गंभीर प्रयास कर रही है। उन्होंने बताया कि दिव्यांगजन सशक्तिकरण, छात्रवृत्ति योजनाएँ, कौशल विकास कार्यक्रम और स्वरोजगार सहायता योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से समाज के कमजोर वर्गों को मुख्यधारा से जोड़ने का काम किया जा रहा है। बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के संयुक्त सचिव तारण प्रकाश सिन्हा एवं आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के आयुक्त डॉ. सरांश मिश्र, रोकित्मा यादव सहित वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।

करेंगुडालु के शूरमाओं के पराक्रम का हुआ यशोगान

अमित शाह ने ऑपरेशन ब्लैक फारेस्ट में शामिल जवानों का किया सम्मान

जगदलपुर

देश के सबसे बड़े एंटी नक्सल अभियान ऑपरेशन ब्लैक फारेस्ट में शामिल वीर जवानों का केंद्रीय गृह एवं सहायता मंत्री अमित शाह ने सम्मान किया है। पहाड़ी पर ऑपरेशन ब्लैक फारेस्ट बस्तर संभाग के बीजापुर जिले और तेलंगाना की सीमा पर स्थित नक्सलियों की सबसे बड़ी पनाहाह करेंगुडालु पहाड़ी पर कई दिनों तक चला था। इस ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम देने वाले सीआरपीएफ छत्तीसगढ़ पुलिस, डीआरजीऔर कोबरा के जवानों से केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने भेंट कर उन्हें सम्मानित किया।

इस अवसर पर शाह ने कहा कि करेंगुडालु पहाड़ी पर चले अब तक के सबसे बड़े नक्सल विरोधी अभियान ऑपरेशन ब्लैक फारेस्ट में वीर जवानों ने शौर्यपूर्ण प्रदर्शन कर अभियान को सफल बनाया, सभी सुरक्षाबलों के जवानों को हृदय से बधाई। उन्होंने कहा कि नक्सलियों के विरुद्ध अभियान के इतिहास में ऑपरेशन ब्लैक फारेस्ट के दौरान जवानों का शौर्य और पराक्रम एक स्वर्णिम अध्याय



के रूप में दर्ज होगा। जब तक सभी नक्सली या तो आत्मसमर्पण न कर दें, पकड़े न जाएं या समाप्त न हो जाएं तब तक चैन से नहीं बैठेंगे, भारत को नक्सलमुक्त बनाकर ही रहेंगे। गर्मी, ऊंचाई और हर कदम पर आईईडी के खतरों के बावजूद सुरक्षाबलों ने बुलंद होसले से अभियान को सफल बनाकर नक्सलियों का बेस कैम्प समाप्त किया। श्री शाह ने कहा- करेंगुडालु पहाड़ी पर नक्सलियों के मैटीरियल डंप और सप्लाई चैन को सुरक्षाबलों के जवानों ने पराक्रम से नष्ट कर दिया। नक्सल विरोधी अभियानों में गंभीर शारीरिक क्षति उठाने वाले सुरक्षाबलों के जीवन को सुचारु रूप से चलाने के लिए मोदी सरकार हरसंभव प्रयास कर रही है। नक्सलविरोधी अभियानों के कारण पशुपतिनाथ से लेकर तिरुपति तक के क्षेत्र में साढ़े 6 करोड़ लोगों के जीवन में नया सूर्योदय हुआ है। नई दिल्ली में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय तथा उप मुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री विजय शर्मा की उपस्थिति में आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में केंद्रीय गृह एवं सहायता मंत्री अमित शाह ने वीर जवानों से भेंट की और उन्हें सम्मानित किया। अमित शाह ने कहा कि

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम भारत को नक्सलमुक्त बनाकर ही रहेंगे।

शौर्य का हुआ बहुमानः
केदार कश्यप

बस्तर के जुझारू एवं युवा आदिवासी नेता केदार कश्यप ने ऑपरेशन ब्लैक फारेस्ट में अपनी जान की बाजी लगाकर नक्सलियों के सबसे बड़े ठिकाने को तबाह करने वाले जवानों को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह द्वारा सम्मानित किए जाने पर खुशी जाहिर की है। केदार कश्यप ने वीर जवानों को बधाई देते हुए कहा है कि भाजपा राष्ट्रवादी पार्टी है और देशभक्त जवानों के उत्साहवर्धन के लिए हमेशा तत्पर रहती है। हमारे राष्ट्र भक्त प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हर बड़े त्यौहार के दौरान सीमाओं पर उठे जवानों के बीच खुशियाँ शेयर करते हैं, उनका सुख दुख साझा करते हैं, हमारे केंद्रीय गृहमंत्री माननीय अमित शाह जी भी देशभक्त फौजी भाइयों के बीच अक्सर पहुँचते रहते हैं।

आरएएमपी योजना के तहत एक दिवसीय कार्यशाला संपन्न

स्थानीय उत्पादों को मिलेगा डिजिटल बाजार

बिलासपुर

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई), महिला उद्यमियों, स्व सहायता समूहों (एसएचजी) और पारंपरिक कारीगरों को डिजिटल माध्यम से बाजार से जोड़ने के उद्देश्य से उद्योग संचालनालय और सीएसआईडीसी, रायपुर की पहल से मंगला चौक स्थित एक निजी होटल में एमएसएमई को ई-मार्केटप्लेस एवम् डिजिटल मार्केटिंग से जोड़ने संबंधी कार्यशाला आयोजित की गई। यह कार्यक्रम भारत सरकार की आरएएमपी योजना के अंतर्गत हुआ।

कार्यशाला का शुभारंभ जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के मुख्य महाप्रबंधक सी.आर. टेकाम की अध्यक्षता में हुआ। उन्होंने कहा कि स्थानीय उत्पादों को डिजिटल



मंचों से जोड़कर राष्ट्रीय और वैश्विक पहचान दिलाई जा सकती है। कार्यशाला में सभ्यशा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म (ओएनडीसी पार्टनर) से शशांक पात्रो ने सभ्यशा मंच पर बीटूबी एवं बीटूसी हेतु विक्रेता पंजीकरण, उत्पाद सूचीकरण, प्रचार-प्रसार, और डिजिटल बाजार के बारे में जानकारी दी। वहीं समविता ई-

कॉमर्स प्लेटफॉर्म (ओएनडीसी पार्टनर) से मोहित शर्मा जी ने उद्यमियों को बीटूबी एवं बीटूसी हेतु विक्रेता पंजीकरण से लेकर डिजिटल बाजार तक की प्रक्रिया समझाई।

डिजिटल मार्केटिंग सत्र में मीमो प्रसाद, निदेशक, इन्टेलिग्रेटर टेक्नोलॉजीस प्रा.लि. रायपुर ने ईडियामार्ट ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर

विक्रेता पंजीकरण के साथ-साथ सोशल मीडिया और मोबाइल ऐप्स के माध्यम से कम लागत में उत्पादों को ब्रांडिंग व बिक्री बढ़ाने के सरल उपाय बताए। उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण तस्वीरें, आकर्षक विवरण और ग्राहकों से नियमित संवाद स्थानीय उत्पादों को वैश्विक ब्रांड बनाने में सहायक है। इस अवसर पर डॉ. योगेश

शर्मा, राज्य परियोजना कार्यान्वयन इकाई, आरएएमपी योजना-सीएसआईडीसी, रायपुर ने राज्य में चल रही आरएएमपी योजना की गतिविधियों जैसे उद्यमिता जागरूकता, निर्यात प्रशिक्षण, डिजिटल विपणन और वित्तीय पहुँच पर विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम में कुल 64 प्रतिभागी उपस्थित रहे, जिसमें महिला उद्यमी, समूह सदस्य, पारंपरिक कारीगर और स्थानीय एमएसएमई प्रतिनिधि शामिल थे। कार्यक्रम में जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र से श्री सत्येन्द्र वर्मा, सुनील कुमार पाण्डेय, छत्रपाल सिंह बिड़वार, आरती झलरिया, रेवती कुमार लहरे, ए. श्रीधर राव प्रबंधक उपास्थित रहे। सभी सत्रों के बाद उद्यमियों के साथ सवाल-जवाब के बाद कार्यशाला का समापन किया गया।



बिलासपुर

निडानिया परिवार द्वारा आयोजित मैरिज गार्डन पर्यटनगांव में चल रही भागवत कथा बुधवार को संपन्न हो गई। कथा आचार्य श्री अंकुश तिवारी जी महाराज लड्डू गोपाल धाम यूपी जी के मुखारविंद से 7 दिन तक चली कथा में भक्तों को श्रीमद् भागवत कथा की महिमा बताई। उन्होंने लोगों से भक्ति मार्ग से जुड़ने और सत्कर्म करने को कहा। उन्होंने कहा कि हवन-यज्ञ से वातावरण एवं वायुमंडल शुद्ध होने के साथ-साथ व्यक्ति को आत्मिक बल मिलता है। व्यक्ति में धार्मिक आस्था जागृत होती है। दुर्गुणों की बजाय सद्गुणों के द्वार खुलते हैं।

यज्ञ से देवता प्रसन्न होकर मनवांछित फल प्रदान करते हैं। उन्होंने बताया कि भागवत कथा के श्रवण से व्यक्ति भव सागर से पार हो जाता है। श्रीमद् भागवत से जीव में भक्ति, ज्ञान एवं वैराग्य के भाव उत्पन्न होते हैं। इसके श्रवण मात्र से व्यक्ति के पाप पुण्य में बदल जाते हैं। विचारों में बदलाव होने पर व्यक्ति के आचरण में भी स्वयं बदलाव हो जाता है। कथावाचक आचार्य ने भंडारे के प्रसाद का भी वर्णन किया। उन्होंने कहा कि प्रसाद तीन अक्षर से मिलकर बना है। पहला प्र का अर्थ प्रभु, दूसरा सा का अर्थ साक्षात् व तीसरा द का अर्थ होता है दर्शन। जिसे हम सब प्रसाद कहते हैं। हर कथा या अनुष्ठान का

तत्वसार होता है जो मन बुद्धि व चित्त को निर्मल कर देता है। मनुष्य शरीर भी भगवान का दिया हुआ सर्वश्रेष्ठ प्रसाद है। जीवन में प्रसाद का अपमान करने से भगवान का ही अपमान होता है। भगवान का लगाए गए पुण्य का बचा हुआ शेष भाग मनुष्यों के लिए प्रसाद बन जाता है। कथा समापन के दिन बुधवार को विधिबिधान से पूजा करवाई। श्रीमद्भागवत कथा सातवें दिन कृष्ण उद्भव संवाद राजा परीक्षित मोक्ष कथा कुरुक्षेत्र प्रसंग सुखदेव पूजन अंतिम में निडानिया परिवार के सदस्य अनिल अग्रवाल ने सभी श्रोताओं के साथ कथा वाचक पूज्य महाराज जी का भी आभार व्यक्त किया।

सीपत पुलिस की त्वरित कार्यवाही सेवा सहकारी समिति में चोरी करने वाले दो आरोपी गिरफ्तार, 80 हजार का सामान बरामद



बिलासपुर

सीपत पुलिस ने ग्राम सौंठी स्थित सेवा सहकारी समिति मर्यादित में हुई चोरी की घटना का खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से कम्प्यूटर, इनवर्टर, बैटरी सहित करीब 80 हजार रुपए की संपत्ति बरामद की गई है। दोनों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।

पुलिस के अनुसार ग्राम सौंठी निवासी प्रहलाद दास वैष्णव ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि अज्ञात चोरों ने सेवा सहकारी समिति की खिड़की तोड़कर कम्प्यूटर, मॉनीटर, सीपीयू, दो इनवर्टर और

एक बैटरी चोरी कर ली है। घटना की जानकारी मिलते ही सीपत थाना प्रभारी ने टीम गठित कर जांच शुरू की।

पुलिस ने संदेही चंदन उर्फ भोलू उर्फ बिसनाथिया दास मानिकपुरी (32 वर्ष) निवासी सौंठी और उसके साथी किशन उर्फ रामू ठाकुर (28 वर्ष) निवासी सौंठी डोहपारा को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ में दोनों ने चोरी की वारदात को अंजाम देना स्वीकार किया। उनकी निशानदेही पर चोरी गया सामान बरामद कर लिया गया।

पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।

एसईसीएल ने अगस्त 2025 में 102 आश्रितों को दिए रोजगार

बिलासपुर

एसईसीएल कंपनी के दिवंगत कर्मियों के आश्रितों को त्वरित रोजगार उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयासरत है। इसी कड़ी में अगस्त 2025 माह में कंपनी ने 102 आश्रितों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए हैं। अगस्त माह में सर्वाधिक 21-21 नियुक्तियाँ बैकुंठपुर और चिरमिरी क्षेत्रों में की गईं। वहीं इस वर्ष अप्रैल 2025 से अब तक कुल 182 आश्रितों को नौकरी दी जा चुकी है। कंपनी द्वारा आश्रितों के प्रकरणों में शीघ्र कार्यवाही करते हुए जल्द से जल्द नियुक्तियाँ सुनिश्चित की जा रही हैं।

कंपनी के मानव संसाधन एवं सतर्कता विभागों के संयुक्त प्रयास से रोजगार प्रक्रिया में विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर विशेष ध्यान



दिया जा रहा है, ताकि आश्रितों को किसी भी प्रकार की कठिनाइयों का सामना न करना पड़े और उनके प्रकरणों का त्वरित

निपटारा हो सके। एसईसीएल प्रबंधन का कहना है कि आश्रितों के प्रति संवेदनशील रहते हुए त्वरित रोजगार उपलब्ध कराना

कंपनी की प्राथमिकताओं में से एक है और भविष्य में भी इस दिशा में प्रयास लगातार जारी रहेगा।

शासकीय हाई स्कूल खारढोढी में मुख्यमंत्री सरस्वती साइकिल योजना के तहत साइकिल वितरण किया गया



पथलगांव

शासकीय हाई स्कूल खारढोढी में मुख्यमंत्री सरस्वती साइकिल योजना के तहत साइकिल वितरण किया गया जिसमें मुख्य अतिथि ग्रामीण मंडल प्रभारी हरजीत सिंह भाटिया, मंडल अध्यक्ष हेमंत बंजारा जी, शाला समिति अध्यक्ष राजेन्द्र बेहरा, मंडल उपाध्यक्ष कौशल धुर्वे, सरपंच दुबराज धुर्वे, नरेश सिलार, युवा मोर्चा अध्यक्ष अरुण यादव, पंच जयसिंह धुर्वे, प्राचार्य विदाल बाज, व्याख्याता नंदकिशोर डनसेना एवं शाला कर्मचारी ग्रामीण जन उपस्थित थे।

सांस्कृतिक, राजनीतिक सामाजिक धरना, प्रदर्शन, रैली अथवा कार्यक्रम की जानकारी पुलिस को जरूर दें: शशि मोहन

पथलगांव

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जशपुर श्री शशि मोहन सिंह द्वारा जिले के सभी *नागरिकों से अपील किया है कि कोई भी सांस्कृतिक, राजनीतिक या सामाजिक धरना, प्रदर्शन, रैली अथवा कार्यक्रम आयोजित* किया जाता है तो उसकी सूचना पूर्व में ही प्रशासन को दिया जाये तभी समुचित पुलिस बल लगाया संभव होता है।

पूर्व सूचना मिलने पर ही आवश्यकतानुसार* पुलिस बल तैनात किया जा सकता है और उचित सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित



की जा सकती है। गणेश विसर्जन के समय की दुर्भाग्यपूर्ण घटना का एक मुख्य कारण यह भी रहा कि *गणेश विसर्जन के साथ निकाले गए डीजे एवं जुलूस की

जानकारी पुलिस एवं जिला प्रशासन को पूर्व में नहीं दी गई थी, जिसके कारण सुरक्षा व्यवस्था लगाना संभव नहीं हो पाया। इस घटना में बड़ी संख्या में लोग घायल हुए तथा मृत्युवान जनहानि हुई, जिस पर जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन गहरा दुःख व्यक्त करता है। अतः पुनः सभी नागरिकों से आग्रह है कि *भविष्य में किसी भी प्रकार का जुलूस/कार्यक्रम आयोजित करने से पूर्व प्रशासन को सूचित करें, ताकि पर्याप्त पुलिस बल* एवं सुरक्षा व्यवस्था लगाई जा सके और ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना को पुनरावृत्ति न हो।

पूर्व सरकार के खाली-बंजर पड़े गोठानों में शुरु हुआ महुआ बचाओ अभियान

मनेंद्रगढ़। वनमंडल के डीएफओ मनीष कश्यप ने विशेष पहल की है। खाली पड़े गोठानों में महुआ बचाओ अभियान के तहत महुआ पौधे लगा के इसको हरा-भरा किया जा रहा है। गोठानों में फेंसिंग पहले से थी, जो चोरी हो रहा था। वन विभाग ने फेंसिंग मरम्मत करके इसमें महुआ के पौधे लगा दिए जिससे ये क्षेत्र अतिक्रमण से बच गया और ग्रामीणों का भविष्य में महुआ से आय भी सुनिश्चित हो गई है। अब तक मनेंद्रगढ़ वनमंडल के 98 गोठान में लगभग 60 हजार महुआ के पौधे रोपे जा चुके हैं। इसके लिए हर ग्राम पंचायत से हड़ल्ट लिया गया और प्रत्येक गोठान में स्थानीय जनप्रतिनिधि ने पौधे लगा के इस अभियान की शुरुवात की।

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने पाँच वर्ष के कार्यकाल में गोबर और गोठान पे विशेष फोकस रखा। बावजूद इसके आज सभी गोठान खाली और बंजर पड़े हैं। हर गाँव में गोठान बनाया गया। छत्तीसगढ़ में लगभग 8 हजार गोठान बनाये गए जिसमें औसतन हर गोठान में 50 लाख तक खर्च किया गया। गाँव के मूलभूत

वनमंडल मनेंद्रगढ़ की विशेष पहल, गोठानों का हो रहा समुचित उपयोग



जरूरत को पूरा ना करके गोठान बनाया गया जिसका कोई फायदा ही नहीं हुआ। ग्रामीण इलाकों में इसका पिछली सरकार का बहुत नकारात्मक छवि बनी। गोठानों में अब अतिक्रमण हो रहा है और असामाजिक तत्वों का ये अड्डा बनते जा रहा है।

महुआ पेड़ों की घटती संख्या चिंता का विषय है। सबसे बड़ी समस्या इनकी पुनरुत्पादन की है। जंगल में तो महुआ पर्याप्त है, पर आदिवासियों के द्वारा अधिक महुआ का संग्रहण गाँव के खाली पड़े जमीन और खेत के मेड़ों पे लगे महुआ से होती है। अगर आप बस्तर और सरगुजा के किसी गाँव

में जाये तो उनके खेतों के पर और खाली जमीन में सिर्फ बड़े महुआ के पेड़ ही बचे दिखते हैं। छोटे और मध्यम आयु के पेड़ लगभग नगण्य होती हैं। ग्रामीणों के द्वारा महुआ संग्रहण से पहले जमीन साफ करने हेतु आग लगाई जाती है, उसी के कारण एक भी महुआ के पौधे जिंदा नहीं रहते। ग्रामीण महुआ के सभी बीज को भी संग्रहण कर लेते हैं, ये भी एक कारण है महुआ के खत्म होने का। आखिर बड़े महुआ पेड़ कब तक जीवित रह पायेंगे ??

छत्तीसगढ़ के महुआ पेड़ बूढ़े हो रहे हैं। महुआ पेड़ की औसत आयु 60 वर्ष है। अगर जंगल के

बाहर इनके पुनरुत्पादन पर ध्यान नहीं दिया गया तो ये जल्द ही खत्म हो जाएँगे। एक महुआ के पेड़ से एक आदिवासी परिवार औसतन 2 किंटल फूल और 50 किलो बीज प्राप्त कर लेता है जिसकी कीमत लगभग 10 हजार होती है। भारत सरकार (पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग) ने भी सभी राज्यों के वन विभाग को पत्र लिखा है कि वृक्षारोपण में महुआ के पौधे ज्यादा से ज्यादा लगाये जाए।

मनेंद्रगढ़ में महुआ बचाओ अभियान की शुरुवात पिछले वर्ष ही हो गई थी। ग्रामीणों को 30 हजार ट्री गार्ड देकर महुआ पौधे लगवाये गए थे। इसका ग्रामीणों में जबरदस्त उत्साह था। इसको देखते हुए इस वर्ष अब तक 1.12 लाख पौधे लगाए जा चुके हैं। जिसमें ग्रामीणों के यहाँ 30 हजार पौधे ट्रीगार्ड में, 22 हजार पौधे बाड़ी में, और 60 हजार पौधे गोठानों में लगाया गया है। ग्रामीण इससे बहुत खुश हैं। इस महुआ बचाओ अभियान

निराश्रित एवं बेसहारा परिवार का सहारा बनी संत रामपाल महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम



दुर्ग

भारतवर्ष में आज भी लाखों लोग ऐसे हैं जो जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित हैं। किसी के पास दो वक की रोटी नहीं, तो कोई छत और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्षरत है। दुर्ग जिला तहसील पाटन के ग्राम जामगांव एम के रहने वाली आशा रात्रे का परिवार भी ऐसी ही कठिन परिस्थिति से जूझ रहा है। तीन सदस्यीय इस परिवार में इनके पति राकेश कुमार का किडनी की गंभीर बीमारी के कारण मीत हो गई है। जिस कारण से घर की समस्त जिम्मेदारी उनकी पत्नी आशा बाई रात्रे के कंधों पर आ गई है, जो खुद मजदूरी कर किसी प्रकार परिवार की गुजर-बसर कर रही

हैं। इस परिवार के पास न खुद का मकान है और न ही किसी प्रकार की स्थायी सहायता। ऐसी ही विषम परिस्थितियों में संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम ऐसे परिवार के लिए उम्मीद की किरण बनकर सामने आई है। 5 अगस्त 2025 को संत रामपाल जी महाराज की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत इस जरूरतमंद परिवार को राहत पहुंचाई गई थी जिसमें आटा, चावल, दाल, तेल, नमक जैसी रोजमर्रा की आवश्यक खाद्य सामग्री 1 महीने की बिल्कुल निःशुल्क प्रदान की गई थी। इसी प्रकार दिनांक 3 अगस्त 2025 को पुनः राशन समान का कीट दिया गया और परिवार को बताया गया कि यह राशन नियमित रूप से तब तक

प्रदान की जाएगी जब तक उनके हालात सामान्य नहीं हो जाते। इस मुहिम के तहत आशा रात्रे का नाम और Contact नंबर भी दर्ज कर लिया गया है, ताकि समय-समय पर और भी सहायता दी जा सके। गाँव के सरपंच सहित कई ग्रामीण जनों ने इस सेवा कार्य की सराहना की। संत रामपाल जी महाराज की ओर से चल रही अन्नपूर्णा मुहिम केवल राहत सामग्री पहुंचाने का कार्य नहीं है, बल्कि मानवता की पुनर्स्थापना का कार्य है। वर्तमान में उनकी अन्नपूर्णा मुहिम देश के कोने-कोने में जरूरतमंदों तक पहुंचाने लगी है। इस मुहिम में जिला संयोजक रमेश साहू, रामनरेश महतो, ब्लॉक संयोजक मुकेश सिन्हा सहित संत रामपाल महाराज के अन्य शिष्य मौजूद थे।

स्वास खबर...

विधानसभा अध्यक्ष विभिन्न

कार्यक्रमों में होंगे शामिल

राजनांदगांव

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह 4 सितम्बर 2025 को राजनांदगांव जिले के प्रवास के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह सुबह 11.45 बजे स्पीकर हाऊस राजनांदगांव से कार द्वारा प्रस्थान कर दोपहर 12 बजे हायर सेकेंडरी स्कूल ग्राम सोमनी पहुंचकर सायकल वितरण एवं नीट व जेईई क्लास का शुभारंभ करेंगे।



विधानसभा अध्यक्ष दोपहर 12.45 बजे ग्राम सोमनी से कार द्वारा प्रस्थान कर दोपहर 1 बजे पंचश्री गोविंदराम निर्मलकर ऑडिटोरियम राजनांदगांव पहुंचकर सहकारी सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल होंगे। विधानसभा अध्यक्ष दोपहर 2.30 बजे पंचश्री गोविंदराम निर्मलकर ऑडिटोरियम राजनांदगांव से कार

द्वारा प्रस्थान कर 2.45 बजे स्पीकर हाऊस राजनांदगांव पहुंचेंगे एवं समय आरक्षित रहेगा। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह दोपहर 3.15 बजे स्पीकर हाऊस राजनांदगांव से कार द्वारा प्रस्थान कर शाम 3.30 बजे ग्राम सुकुलदेहान पहुंचकर भूमिपूजन कार्यक्रम में शामिल होंगे। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह शाम 4.30 बजे ग्राम सुकुलदेहान से कार द्वारा प्रस्थान कर शाम 4.45 बजे स्पीकर हाऊस राजनांदगांव पहुंचेंगे एवं समय आरक्षित रहेगा। विधानसभा अध्यक्ष रात्रि 8 बजे स्पीकर हाऊस राजनांदगांव से स्पीकर हाऊस शंकर नगर रायपुर के लिए प्रस्थान करेंगे।

निजी स्कूल में हुई मारपीट मामले की घटना को बताया गंभीर, युवा नेताओं ने रखी शिकायत

राजनांदगांव

राजनांदगांव के निजी स्कूलों में हुई मारपीट की घटना को जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई इसके बाद एनएसयूआई संगठन की ओर से मामले को संज्ञान में लेते हुए जिला शिक्षा अधिकारी को लिखित शिकायत कर मामले की जांच कर कार्यवाही को लेकर पत्र लिखा है युवा नेता ऋषि शास्त्री ने बताया कि सोशल मीडिया के माध्यम से बीते कुछ दिन पहले हुए एक निजी स्कूलों में मारपीट की घटना पर विकासखंड शिक्षा अधिकारी द्वारा बयान आया की उन्हें ऐसी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है जानकारी मिलने पर कार्यवाही करेंगे इसी तारतम में हमने आज जिला शिक्षा अधिकारी को पत्र लिखा है मामले को गंभीर बताया हुए संबंद में जानकारी भी मांगी है हालही में स्कूल शिक्षा के विषय में काफी सारी समस्या परिनज एवं विद्यार्थियों से प्राप्त होते आई है जिसे हल करने हमारे द्वारा हर स्तर तक प्रयास किया जाता आया है शास्त्री ने बताया की यह शिकायत भी मिली की आत्मानंद स्कूलों में तिमिही परीक्षा हो जाने के बावजूद भी किताबें नहीं पहुंच पाई है जिसको लेकर पाठ्य पुस्तक निगम को जानकारी देकर जिन विषयों की पुस्तक नहीं पहुंच पाई हैं उनकी जानकारी स्कूल से मांगने और तत्काल किताबों की व्यवस्था करने कहा गया है ऐसा ही एक और विषय सामने आया जिसमें शिक्षा के अधिकार के तहत पढ़ रहे विद्यार्थियों से बैंक के अधिकारियों जा रही है जिस पर संबंधित अधिकारी को संबंधित शुल्क के संबंध में नियमानुसार सभी निजी स्कूलों में नोटिस जारी करने सहित शिक्षा के अधिकार के तहत पढ़ रहे बच्चों को जो सुविधा दी जानी है इसका उल्लेख करते हुए निर्देश जारी करने कहा गया है।

अतिक्रमण के नाम पर हटाए गए फुटकर दुकानदारों को व्यवस्थित करें: कुलबीर



राजनांदगांव

शहर के फलाई ओव्हर के नीचे कई वर्षों से छोटे व्यवसायियों अपने रोजगार के तहत चाय-ठेले, चाट-ठेले, गाड़ियों के रिपैरिंग कर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे थे, जिसे भाजपाईयों के दबाव पर प्रशासन द्वारा अतिक्रमण के तहत दुकान को हटाया दिया गया जिसके कारण वहां पर लगा रहे फुटकर व्यवसायियों बेरोजगार हो गए जिस कारण उनके रोजगार की समस्या व परिवार के पालन पोषण की बड़ी आपदा हो गई। जिसको लेकर शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में सोमवार 01 सितंबर को निगम आयुक्त अतुल विश्वकर्मा को ज्ञापन सौंपकर तत्काल फुटकर व्यवसायियों पुनर्स्थापित करने की मांग की। शहर कांग्रेस कमेटी के महामंत्री अमित चंद्रवंशी ने विज्ञप्ति जारी करते हुए बताया कि फुटकर दुकानदारों प्रशासन द्वारा अतिक्रमण के तहत हटाया दिया गया है। जिससे उनका रोजगार छिन गया रोजी-रोटी की समस्या खड़ी हो गई जिसको लेकर शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर फुटकर व्यवसायियों को पुनर्स्थापित करने की मांग की।

कलेक्टर की अध्यक्षता में राजस्व अधिकारियों की हुई समीक्षा बैठक

कोरबा। कलेक्टर अजीत वसंत की अध्यक्षता में राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। उन्होंने तहसीलवार राजस्व प्रकरणों के निराकरण की अद्यतन स्थिति की विस्तृत समीक्षा करते हुए लंबित सभी राजस्व प्रकरणों के निराकरण में प्रगति लाने के निर्देश दिए। बैठक में अनुविभागीय अधिकारी कटघोरा श्री तन्मय खन्ना, अपर कलेक्टर श्री देवेंद्र पटेल, सभी एसडीएम, प्रभारी अधिकारी भू अभिलेख, अधीक्षक भू अभिलेख, सभी तहसीलदार और नायब तहसीलदार उपस्थित थे। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित बैठक में कलेक्टर ने तहसीलदारों को विशेष प्रयास करने एवं गम्भीरता से प्रगति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने तीन वर्ष या उससे अधिक समय से लंबित भू अर्जन सहित अन्य राजस्व प्रकरणों को शीघ्रता से निराकृत करने की बात कही। कलेक्टर ने तहसीलदारों को कौतव्य भूमि, शासकीय पट्टे, भू अर्जन एवं खनिज प्रभावित क्षेत्रों की भूमि के खसरे में अहस्तांतरणीय दर्शाना सुनिश्चित करने की बात कही। जिससे उक्त भूमि की खरीदी विक्री पर कोट लगाई जा सके (उन्होंने सभी विकासखंडों में मसालेदार ग्राम के सर्वे व नक्शा प्रकाशन को वर्तमान स्थिति के संबंध में जानकारी लेते हुए एन नक्शा प्रकाशन के कार्य में तेजी लाने के लिए कहा।

दुर्ग एवं बस्तर संभाग के 650 तीर्थ यात्रियों को हरी झंडी दिखाकर स्पेशल ट्रेन से किया रवाना

प्रभु श्रीराम के दर्शन के लिए राजनांदगांव रेलवे स्टेशन से जाने वाले दर्शनार्थियों में भारी उत्साह एवं खुशी का क्षण

राजनांदगांव

पर्यटन, संस्कृति, धार्मिक न्याय एवं धर्मस्व मंत्री राजेश अग्रवाल ने आज रेलवे स्टेशन राजनांदगांव से श्री रामलला दर्शन अयोध्या धाम योजना अंतर्गत दुर्ग एवं बस्तर संभाग के 13 जिलों के 650 तीर्थ यात्रियों को हरी झंडी दिखाकर तीर्थयात्री विशेष ट्रेन को रवाना किया। राज्य शासन की महत्वपूर्ण श्री रामलला दर्शन अयोध्या धाम योजना अंतर्गत प्रभु श्रीराम के दर्शन के लिए राजनांदगांव रेलवे स्टेशन से जाने वाले दर्शनार्थियों में भारी उत्साह एवं खुशी का क्षण रहा। जयश्री राम के जयकारे के साथ ढोल-मंजीरे की मंगल ध्वनि के साथ श्रद्धालुओं को अयोध्या के लिए विदा किया गया। पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि सदियों से प्रभु श्री राम की महिमा जनमानस में व्याप्त है।



अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर स्थापित होने के बाद दर्शनार्थियों को अयोध्या जाकर दर्शन करने की इच्छा होती है। मंत्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की मंशा के अनुरूप निःशुल्क प्रभु श्री

रामलला दर्शन कराया जा रहा है। पिछले वर्ष 26 ट्रेनों के माध्यम से 22 हजार 100 से अधिक दर्शनार्थियों को दर्शन कराया गया। इस वर्ष अब तक 6 हजार से अधिक दर्शनार्थियों ने दर्शन का लाभ लिया है और आगे लगातार दर्शन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि दर्शनार्थियों के दर्शन से हम सभी को दर्शन का लाभ एवं पुण्य मिलेगा। प्रदेश के 850 से अधिक दर्शनार्थी दर्शन करके आएंगे तो 85 हजार लोगों को इसका लाभ मिलेगा। मंत्री राजेश अग्रवाल ने सभी दर्शनार्थियों को तीर्थ यात्रा के लिए मंगलकामना एवं शुभकामनाएं दी। सांसद संतोष पाण्डेय ने कहा कि हम सब का सौभाग्य है कि भगवान श्री राम जिनका मामा गांव छत्तीसगढ़ है और यह कौशल प्रदेश है। केन्द्र एवं राज्य शासन की हमेशा इच्छा रही है कि पर्यटन, देशाटन होता रहे।

उन्होंने सभी दर्शनार्थियों को यात्रा के लिए शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित के अध्यक्ष सचिन बघेल, अध्यक्ष जनपद पंचायत प्रतिमा चंद्राकर, जिला पंचायत सदस्य देवकुमारी साहू, पूर्व विधायक विनोद खाण्डेकर, खूबचंद पारख, रमेश पटेल, संतोष अग्रवाल, कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे, अपर कलेक्टर प्रेमप्रकाश शर्मा, एसडीएम खेमलाल वर्मा सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी उपस्थित थे।

व्यापारी संघ एक्सिस बैंक के सहयोग से लोन सिका वितरण मेला



रायपुर

महादेव घाट रोड व्यापारी कल्याण संघ एवं एक्सिस बैंक शाखा सुंदर नगर के संयुक्त तत्वाधान में व्यापारियों के लिए विभिन्न प्रकार के लोन जिसमें बिजनेस लोन पर्सनल लोन व्हीलक लोन हाउसिंग लोन मुद्रा लोन मांडेज लोन ओडी अकाउंट गोल्ड लोन इश्योरेंस का मेला लगाया गया जिसमें बहुत से दुकानदारों द्वारा लोन के संबंध में बैंक के अधिकारियों से चर्चा की गई इसके साथ ही एक्सिस बैंक शाखा सुंदर नगर के द्वारा तो 2/5/10 के सिक्के का वितरण क्षेत्र के हर व्यापारियों व्यापार में फिक्कत परेशानी को देखते हुए वितरण

किया गया जिसमें क्षेत्र के 200 व्यापारियों ने लाभ उठाया और एक्सिस बैंक के कार्यों को साहजना करते हुए अच्छी योजनाओं के लिए उन्हें शुभकामनाएं दी इस दौरान विनोद कुमार एक्सिस बैंक मुख्य कार्यालय मुंबई को पुष्प गुच्छ स्मृति चिन्ह प्रशांत अच्यं शाखा स्मृति चिन्ह सुंदर नगर नूतन लोन मांडेज लोन ओडी अकाउंट गोल्ड लोन इश्योरेंस का मेला लगाया गया जिसमें बहुत से दुकानदारों द्वारा लोन के संबंध में बैंक के अधिकारियों से चर्चा की गई इसके साथ ही एक्सिस बैंक शाखा सुंदर नगर के द्वारा तो 2/5/10 के सिक्के का वितरण क्षेत्र के हर व्यापारियों व्यापार में फिक्कत परेशानी को देखते हुए वितरण

मोर मकान मोर आस योजनांतर्गत लॉटरी के माध्यम से मिलेगा स्वयं का आवास

राजनांदगांव

प्रधानमंत्री आवास योजना के षटक मोर मकान मोर आस एक संवेदनशील पहल इसके अंतर्गत मात्र किफायती दरों में आवास के लागत मूल्य पर वर्षों से किरायेदारों के रूप में निवासरत परिवारों का अब सपना साकार हो रहा है। उन्हें स्वयं का अपना पक्का आवास मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजनांतर्गत नगर निगम सीमाक्षेत्र में सुन्दर सुविधायुक्त 1340 बहु मंजिला आवास लखोली, पेण्ड्री, मोहारा, रेवाड़ीह आदि स्थानों में पूर्ण रूप से निर्मित किया है, एवं 590 आवास विभिन्न स्तरों पर निर्माणाधीन है। उक्त आवासों को मोर मकान मोर आस योजना के तहत शासन द्वारा निर्धारित किए गए दरों पर नियमानुसार आर्बिटिट किया जा रहा है। आवास आर्बिटिट करने नगर निगम द्वारा प्रक्रिया की जा रही है। पूर्व में 91 पात्र



हितग्राहियों को आवास का आर्बिटिट किया गया। परियोजना अनुरूप राशि जमा करने पर आवेदकों को लॉटरी के माध्यम से आवास आर्बिटिट किये जायेंगे। आवास आर्बिटिट के संबंध में नगर निगम आयुक्त श्री अतुल विश्वकर्मा ने बताया कि मोर मकान मोर आस योजनांतर्गत वर्षों से किराये में निवासरत परिवारों को आवास उपलब्ध कराया जा रहा है। जिसके लिए नगर निगम द्वारा आवेदन आमंत्रित किया गया है। दावा आपत्ति उपरांत 822 पात्र आवेदक में से परियोजना अनुरूप राशि जमा करने के उपरांत लॉटरी

के माध्यम से आवास का आर्बिटिट किया जायेगा। उन्होंने बताया कि रेवाड़ीह मोहारा 340 युनिट की राशि 2,67,971.00 रुपये निर्धारित है। योजनांतर्गत जिन परियोजनाओं में आवास निर्माण कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं अर्थात् ऐसे आवास जो हितग्राहियों को आर्बिटिट हेतु पूर्ण रूप से तैयार है उन आवासों में हितग्राहियों को हितग्राही अंशदान की राशि एकमुक्त अग्रिम जमा करनी होगी। आयुक्त श्री विश्वकर्मा ने बताया कि वे आवास जो अधीन निर्माणाधीन हैं उन निर्माणाधीन आवास के लिए लॉटरी के पूर्व निर्धारित प्रति आवास मूल्य का 10

प्रतिशत एवं पेश राशि 10 माह में किस्तों के रूप में देनी होगी। निकाय अंतर्गत निर्माणाधीन आवास 272 युनिट लखोली में 2,74,044.00 रू. 258 युनिट रेवाड़ीह, पेण्ड्री में 2,91,027.00 रू. 870 युनिट पेण्ड्री एवं मोहारा में 2,80,115.00 रू. निर्धारित है। आयुक्त श्री विश्वकर्मा ने नागरिकों से अपील करते हुये कहा कि आवास आर्बिटिट के लिये बिचौलियों से बचे, आवास लिये किसी भी व्यक्ति से पैसे का लेनदेन ना करें आवास भुगतल या नीचे ऊपर दिलाने के लिए भी किसी से संपर्क कर किसी को भी पैसा न देवे। बाहरी व्यक्तियों के द्वारा आवास दिलाने संपर्क किया जा रहा है, इस प्रकार की शिकायतें लगातार निगम कार्यालय को प्राप्त हो रही है किसी भी व्यक्ति से इस संबंध में चर्चा कर पैसे का लेनदेन ना करें। क्योंकि वे व्यक्ति निगम से संबंधित नहीं है।

गणपति सेवा पंडाल में हुआ वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान

राजनांदगांव

शहर के पास इलाके लक्ष्मी नगर कालोनी में गणेश उत्सव पूरे धूमधाम से मनाया जा रहा है। समाज से जुड़े हर वर्ग के लोगों को गणेश उत्सव से जोड़ने के लिए कालोनी निवासी लगातार रोज नए आयोजन कर रहे हैं। गणपति बप्पा की स्थापना के दिन से ही रोजाना संध्या आरती के बाद समाज को एक सूत्र में जोड़े रखने के लिए नित्य नए आयोजन कर रहे हैं।

मिली जानकारी के अनुसार लक्ष्मी नगर कालोनी गणेश उत्सव समिति ने समाज को एक सूत्र में पिरोकर रखने के लिए गणेश पंडाल में रोजाना संध्या आरती के बाद एक अलग आयोजन कर रहे हैं। इनमें पहला दिन आर्केस्ट्रा का आयोजन किया गया। जिसमें शहर के लोगों को भक्ति की धुन में



अपनी आवाज लोगों तक पहुंचाने के लिए एक मंच प्रदान किया गया। इस मंच के माध्यम से समाज के हर तबके को गणेश उत्सव से जोड़ने की कोशिश की गई। आयोजन में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया और भक्ति रस में डूबे हुए गीत संगीत आनंद लिया। आयोजन की श्रृंखला में दूसरे दिन शहर के वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान किया गया। इस कड़ी में

शहर के वरिष्ठ नागरिक श्रीमती लव शुक्ला, आशा झा, अनिल मिश्रा, पुष्पा बवेजा, ग्वालु, श्रीमती रामबाई साहू, श्रीमती शशि ठाकुर, सरस्वती बक्शी, आशा मांडेवर, श्रीमती रुक्मणी साहू, बीआर साहू सहित अन्य का सम्मान किया गया है। मंगलवार को भजन संध्या के आयोजन किया गया इस आयोजन में भजन में रुचि रखने वाले लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसके

साथ ही गोंदिया से आई भजन संध्या की टीम ने भी अपनी जोरदार प्रस्तुति दी। जिसे सुनकर कालोनी के निवासी मंत्र मुक्त हो गए। गणेश उत्सव के इस आयोजन में छत्तीसगढ़ राजपूत महासभा के संजय बहादुर सिंह, छत्तीसगढ़ राजपूत महासभा वीरगंगा अध्यक्ष सुषमा सिंह, अमित झा, प्रकाश शुक्ला, मनोप मेजरवार का विशेष सहयोग रहा।

ग्राम डिलापहरी में ग्राम सभा का गठन ग्रामीण हित में लिए गए अहम फैसले

राजनांदगांव

ग्राम डिलापहरी में ग्राम सभा की बैठक आयोजित की गई। जिसमें ग्राम सभा अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष व सदस्यों का गठन किया गया। बैठक में ग्रामीण हितों की रक्षा व अनुशासन बनाए रखने के लिए कई महत्वपूर्ण नियमों पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।

नरेंद्र वर्मा, खेलन वर्मा, लक्ष्मी नारायण वर्मा और अरुण वर्मा शामिल किए गए। यदि कोई ग्रामीण अपने पालतू पशुओं को गौदान की जगह खेतों में छोड़ता है और वे किसी अन्य के खेत में पाए जाते हैं, तो पशु मालिक से 2500 का दंड लिया जाएगा। इसमें 2300 पकड़ने वाले को तथा 200 ग्राम सभा को जमा करना होगा। दंड नहीं देने पर ग्राम सभा द्वारा 1000 का अतिरिक्त दंड लगाया जाएगा।

ग्राम सभा के अध्यक्ष पद पर गेस नारायण वर्मा, कोषाध्यक्ष पद पर सचिव सहदेव वर्मा, कोषाध्यक्ष सुरेश वर्मा को मनोनीत किया गया। इसके साथ ही सदस्य गण में गोविंद नारायण वर्मा, सरपंच उमेश वर्मा, छत्र कुमार वर्मा पंच, दिनेश वर्मा, जितेश्वर यादव, रेखा लक्ष्मण, श्यामराज साहू, गेंदराम साहू, परसराम वर्मा, मनसुख नेम,

व्यक्ति स्कूल परिसर या किसी सरकारी परिसर में शराब पीते पाया गया, तो उस पर भी दंड लगाया जाएगा। सूचित करने वाले को 2300 और 2000 ग्राम सभा को जमा होंगे। धनराशि देने से इंकार करने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों ने इन निर्णयों को सर्वसम्मति से पारित किया।

सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा विषय पर जिला स्तरीय वाद-विवाद प्रतियोगिता संपन्न

विकासखंड डोंगरगढ़ के विद्यालय प्रथम स्थान पर रहे विजयी, प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त दल संगम स्तर पर देगे प्रस्तुति

राजनांदगांव

जिला साक्षरता मिशन प्राधिकरण राजनांदगांव द्वारा जिले के सभी विकासखंड में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने एवं जन जागरूकता लाने के उद्देश्य से सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा विषय पर जिला स्तरीय वाद-विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जिसमें चारों विकासखंडों से 12 दलों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता में जिले के चारों विकासखंड के प्रतिभागियों ने शानदार प्रदर्शन किया। डोंगरगढ़ विकासखंड से प्रतिनिधित्व करते हुए तीनों दलों ने शानदार प्रदर्शन किया। डोंगरगढ़ विकासखंड के दो दलों ने श्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त किया। 6 सितंबर को आयोजित



होने वाले संभाग स्तरीय प्रतियोगिता के लिए अपना स्थान पक्का कर लिया है। प्रथम स्थान प्राप्त दल में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बोरतलाव, अंडी, हाई स्कूल बरनाराकला, सेंदरी के छात्र और द्वितीय स्थान

प्राप्त दल में शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला बागरेकसा, बानादी और चारभाटा के छात्र सम्मिलित थे। इसी प्रकार तृतीय स्थान शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला रीवागहन विकासखंड राजनांदगांव ने प्राप्त किया। विजयी

दलों को 7 हजार रूपए, 5 हजार रूपए, 3 हजार रूपए सम्मान राशि, स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया। सात्वना पुरस्कृत विजेता महाश्री लक्ष्मीबाई कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय राजनंदगांव, डॉ. बलदेव प्रसाद

मिश्र शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बसंतपुर राजनंदगांव, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पिनकापार छुरिया, सेजेस अंग्रेजी माध्यम डोंगरगांव, सेजेस हिंदी माध्यम डोंगरगांव कुल पांच टीमों को प्रति टीम 2 हजार रूपए

सम्मान राशि एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। इस अवसर पर विजयी दलों को जिला शिक्षा अधिकारी श्री प्रवास सिंह बघेल एवं जिला परियोजना अधिकारी श्रीमती रश्मि सिंह ने बधाई और शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में पार्थद श्री शेखर यादव, खेमिन यादव विशेष रूप से उपस्थित थे। इस अवसर पर निर्णायक के रूप में यातायात प्रभारी श्री नवरतन कश्यप, जन शिक्षण संस्थान राजनांदगांव के निदेशक श्री शालम सिंह, सहायक परियोजना सामान्य समग्र शिक्षा राजनंदगांव श्री आदर्श वासनिक, श्रीमती प्रिण्ता शर्मा, श्री मनोज मरकाम, व्याख्याता शास्त्री उच्चतर माध्यमिक विद्यालय धानपुरी श्रीमती शीतल दास, व्याख्याता सेजेस डोंगरगांव श्रीमती नेहा साहू ने अपनी सेवाएं दी।

भारत का आर्थिक मंथन और विकास का अमृत



हरदीप एस. पुरी

जीडीपी के ताजा आंकड़ों पर जरा गौर करें। वित्तीय वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में वास्तविक जीडीपी 7.8 प्रतिशत की दर से बढ़ी। यह वृद्धि दर पिछली पांच तिमाहियों में सबसे अधिक है। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह वृद्धि व्यापक है: सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) 7.6 प्रतिशत बढ़ा है, जिसमें नैन्यूफैब्रिकेशन 7.7 प्रतिशत, निर्माण 7.6 प्रतिशत और सेवा क्षेत्र लगभग 9.3 प्रतिशत बढ़ा है। नॉमिनल जीडीपी में 8.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह कोई मनमाने तरीके से बताई गई तेजी नहीं है। यह बढ़ते उपभोग, मजबूत निवेश और निरंतर सार्वजनिक पूंजीगत व्यय व पूरी अर्थव्यवस्था में लागत कम करने वाले लाइजिस्टिक्स संबंधी सुधारों से हासिल नतीजों का सबूत है।

भारतीय सभ्यता में अरसे से यह मान्यता रही है कि कामयाबी से पहले परीक्षा होती है। समुद्र मंथन, जहां मंथने की प्रक्रिया से अमृत निकला था, इसी तरह हमारे आर्थिक मंथन ने भी हमेशा ही नवीनता का मार्ग प्रशस्त किया है। वर्ष 1991 के संकट से जहां उदारीकरण का जन्म हुआ; वहीं महामारी से डिजिटल उपयोग तेज हुआ। और आज, भारत को एक 'मृत अर्थव्यवस्था' कहने वाले संशयवादियों के शोर-शराबे के बीच - तीव्र विकास, मजबूत बफर, और व्यापक अवसर - की एक तथ्यपरक कहानी उभर कर सामने आई है।

जीडीपी के ताजा आंकड़ों पर जरा गौर करें। वित्तीय वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में वास्तविक जीडीपी 7.8 प्रतिशत की दर से बढ़ी। यह वृद्धि दर पिछली पांच तिमाहियों में सबसे अधिक है। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह वृद्धि व्यापक है: सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) 7.6 प्रतिशत बढ़ा है, जिसमें नैन्यूफैब्रिकेशन 7.7 प्रतिशत, निर्माण 7.6 प्रतिशत और सेवा क्षेत्र लगभग 9.3 प्रतिशत बढ़ा है। नॉमिनल जीडीपी में 8.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह कोई मनमाने तरीके से बताई गई तेजी नहीं है। यह बढ़ते उपभोग, मजबूत निवेश और निरंतर सार्वजनिक पूंजीगत व्यय व पूरी अर्थव्यवस्था में लागत कम करने वाले लाइजिस्टिक्स संबंधी सुधारों से हासिल नतीजों का सबूत है।

भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी और सबसे तेज गति से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था है। यह तेजी के मामले में दुनिया की पहली और दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं क्रमशः अमेरिका और चीन से भी आगे निकल गई है। वर्तमान गति से, हम इस दशक के अंत तक जर्मनी को पीछे छोड़कर बाजार-विनिमय के संदर्भ में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर हैं। हमारी गति वैश्विक स्तर पर मायने रखती है। स्वतंत्र अनुमान बताते हैं कि भारत पहले से ही वैश्विक वृद्धि में 15 प्रतिशत से अधिक का योगदान दे रहा है। प्रधानमंत्री ने एक स्पष्ट लक्ष्य रखा है - सुधारों के मजबूत होने और नई क्षमताओं के सामने आने के साथ-साथ वैश्विक वृद्धि में हमारी हिस्सेदारी बढ़कर 20 प्रतिशत तक पहुंचे। विभिन्न बाजारों और रेटिंग एजेंसियों ने हमारे इस अनुशासन को मान्यता दी है। एसएंडपी ग्लोबल ने मजबूत विकास, मौद्रिक विवशनीयता और राजकोषीय सुरक्षा की सराहना का हवाला देते हुए, 18 वर्षों में पहली बार भारत की 'सांवरन



रेटिंग' को उन्नत किया है। इस अपग्रेड से उधार लेने की लागत कम होती है और निवेशक आधार का विस्तार होता है। यह 'मृत अर्थव्यवस्था' की धारणा को भी झुटलाता है। जोखिम के स्वतंत्र मूल्यांकनकताओं ने अपनी रेटिंग के साथ अपना मत दिया है।

उतना ही महत्वपूर्ण सवाल यह भी है कि आखिर इस सबका लाभ किसे मिला है। वर्ष 2013-14 और 2022-23 के बीच, 24.82 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकल आए हैं। यह बदलाव उन बुनियादी सेवाओं - बैंक खाते, रसोई के लिए स्वच्छ ईंधन, स्वास्थ्य बीमा, नल का जल और प्रत्यक्ष हस्तान्तरण - की बड़े पैमाने पर आपूर्ति पर निर्भर है जो गरीबों को विकल्प चुनने का अधिकार देता है। दुनिया के सबसे जीवंत लोकतंत्र और उल्लेखनीय जनसांख्यिकीय चुनौतियों के बीच विकास का यह पैमाना बेहद खास है। विकास का भारत का यह मॉडल आम सहमति के निर्माण, प्रतिस्पर्धी संघवाद और डिजिटल माध्यमों के उपयोग से अंतिम छोर तक सेवा प्रदान करने को महत्व देता है। यह घोषणा के मामले में धीमा, क्रियान्वयन के मामले में तेज और निर्माण की दृष्टि से टिकाऊ है। जब आलोचक हमारी तुलना तेज भागने वाले सत्तावादियों से करते हैं, तो वे इस तथ्य को नजर अंदाज कर देते हैं कि हम मैराथन धावक की तर्ज पर लंबी दूरी तय करने वाली एक

अर्थव्यवस्था का निर्माण कर रहे हैं। भारत के पेट्रोलियम मंत्री के रूप में, मैं इस बात की पुष्टि कर सकता हूँ कि हमारी ऊर्जा सुरक्षा इस तीव्र विकास में किस प्रकार सहायक की भूमिका निभा रही है। आज, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता, चौथा सबसे बड़ा तेलशोधक (रिफाइनर) और एलएनजी का चौथा सबसे बड़ा आयातक है। हमारी तेलशोधन (रिफाइनिंग) क्षमता 5.2 मिलियन बैरल प्रतिदिन से अधिक है और इस दशक के अंत तक इसे 400 मिलियन टन प्रति वर्ष (एमटीपीए) से आगे बढ़ाने का एक स्पष्ट रोडमैप हमारे पास उपलब्ध है।

भारत की ऊर्जा संबंधी मांग - जो 2047 तक दोगुनी होने का अनुमान है - बढ़ती वैश्विक मांग का लगभग एक-चौथाई हिस्सा होगी, जिससे हमारी सफलता वैश्विक ऊर्जा स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण बन जाएगी। सरकार का दृष्टिकोण सुरक्षा को सुधार के साथ जोड़ने का रहा है। तेल की खोज का क्षेत्र 2021 में तलछटी घाटियों के 8 प्रतिशत से बढ़कर 2025 में 16 प्रतिशत से अधिक हो गया है। हमारा लक्ष्य 2030 तक इसे बढ़ाकर 10 लाख वर्ग किलोमीटर करना है। तथाकथित 'निषिद्ध' (नो-गो) क्षेत्रों में 99 प्रतिशत की भारी कमी ने अपार संभावनाओं को जन्म दिया है, जबकि ओपन एकरेज लाइसेंसिंग पॉलिसी

(ओएएलपी) पारदर्शी व प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया सुनिश्चित करती है। गैस मूल्य निर्धारण से संबंधी नए सुधारों - जिनमें कीमतों को भारतीय कच्चे तेल की टोकरी से जोड़ा गया है और गहर पानी एवं नए कुओं के लिए 20 प्रतिशत प्रीमियम की पेशकश की गई है - ने निवेश को बढ़ावा दिया है। हमारी ऊर्जा की कहानी सिर्फ हाइड्रोकार्बन की ही नहीं, बल्कि बदलाव की भी कहानी है। वर्ष 2014 में इथेनॉल मिश्रण 1.5 प्रतिशत से बढ़कर आज 1.25 लाख करोड़ रुपये से अधिक की विदेशी मुद्रा की बचत के बराबर हो गई है और किसानों को सीधे एक लाख करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान हुआ है। सतत के तहत 300 से ज्यादा संपीड़ित बायोगैस संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं, जिनका लक्ष्य 2028 तक 5 प्रतिशत मिश्रण का है और तेल से जुड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हरित हाइड्रोजन के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं।

भारत द्वारा रूस से कच्चे तेल की खरीद को लेकर कुछ जगहों में काफी शोरगुल हुआ है। आइए तथ्यों को इस शोरशराबे से अलग करके देखें। रूस की तेल पर इरान या वेनेजुएला के कच्चे तेल की तरह कभी प्रतिबंध नहीं लगाया गया। यह जी7/ईयू मूल्य-सीमा प्रणाली के अंतर्गत है जिसे जानबूझकर राजस्व को सीमित रखते हुए तेल प्रवाह को बनाए रखने के लिए डिजाइन किया गया है। ऐसे पैकेजों के 18 दौर हो चुके हैं और भारत ने हर एक दौर का पालन किया है। प्रत्येक लेंदेन में कानूनी लदान (शिपिंग) एवं बीमा, अनुपालन करने वाले व्यापारियों और लेखा-परीक्षण (ऑडिट) किए गए चैनलों का उपयोग किया गया है। हमने कोई नियम नहीं तोड़े हैं। हमने बाजारों को स्थिर किया है और वैश्विक कीमतों को बढ़ने से रोका है।

कुछ आलोचकों का आरोप है कि भारत रूस के तेल के लिए एक 'लॉन्गमैट' बन गया है। इसमें अधिक निराधार बात और कुछ नहीं हो सकती। भारत इस संघर्ष से काफी पहले दशकों से पेट्रोलियम उत्पादों का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक रहा है और हमारे रिफाइनर विश्व भर से इस प्रकार के कूट का एक समूह बनाते हैं। निर्यात आपूर्ति श्रृंखलाओं को सक्रिय रखता है। वास्तव में, रूस के कच्चे तेल पर प्रतिबंध लागू करने के बाद यूरोप ने भी भारतीय ईंधनों की ओर रुझा किया। निर्यात की मात्रा और रिफाइनिंग मार्जिन (जीआरपी) मोटे तौर पर समान ही हैं। मुनाफे लेने का इसमें का कोई सवाल ही नहीं है।

संपादकीय

संभावनाओं भरी मुलाकात

शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के शिखर सम्मेलन से इतर तियानजिन में हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफंग की मुलाकात से भारत में उत्साह का माहौल है। यह मुलाकात द्विपक्षीय संबंधों को सामान्य बनाने के प्रयासों पर ही अधिक केंद्रित रही। पूर्वी लद्दाख में सीमा गतिरोध के बाद से ही दोनों देशों के संबंधों में इतना तनाव आ गया था कि मोदी और शी की मुलाकात से ही उम्मीदें जगने लगी हैं। मोदी 2020 में हुए इस विवाद के बाद पहली बार चीन पहुंचे हैं। हालांकि दोनों नेता पिछले साल रूस के कजान में भी मिले थे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के छोड़े टैरिफ 'युद्ध' से मची उथल-पुथल के बीच बेहद सावधानी से हुए संवाद में दोनों नेताओं ने खूब अच्छी अहम बातें कहीं। मोदी ने कहा कि भारत आपसी विश्वास, सम्मान एवं संवेदनशीलता के आधार पर चीन के साथ अपने संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। दोनों देशों के विशेष प्रतिनिधि सीमा प्रबंधन पर भी एक समझौते पर पहुंच गए हैं। केलास मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू हो गई है। दोनों देशों के बीच सीमा उड़ानें भी फिर से शुरू हो रही हैं। विश्व अर्थव्यवस्थाओं के रूप में भारत और चीन का विश्व आर्थिक व्यवस्था में स्थिरता लाने के लिए मिलकर काम करना महत्वपूर्ण है। वहीं चीन के राष्ट्रपति शी चिनफंग ने एक कदम आगे बढ़कर कहा कि दोनों देशों का 'मित्र' बनना सही विकल्प है तथा 'हाथी' (भारत) एवं 'ट्रेन' (चीन) को एक-दूसरे की सफलता का मिलकर जश्न मनाना चाहिए। चीन और भारत एक-दूसरे के लिए खतरा नहीं बल्कि विकास के अवसर हैं। दुनिया इस समय ऐसे बदलावों से गुजर रही है जो सदी में एक बार होते हैं। मोदी और शी की मुलाकात पर सवाल भी उठे हैं। कांग्रेस का कहना है कि सेना प्रमुख ने लद्दाख में सीमा पर यथास्थिति की पूर्ण बहाली की मांग की थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और मोदी सरकार चीन के साथ सुलह की दिशा में कदम बढ़ा रही है। इससे उस क्षेत्र में चीन की आक्रामकता को अप्रत्यक्ष रूप से वैधता मिल गई है। लगता है इसी साल 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान पाकिस्तान के साथ चीन की जुगलबंदी को क्या हमने भुला दिया है। कुल मिलाकर जहां यह माना जा रहा था कि यह मुलाकात ट्रंप को करारा जवाब देने का मार्ग प्रशस्त करेगी तो इस बारे में साफ-साफ कोई रणनीति नहीं बनी है। कारण यह कि भारत रूस-चीन को साधना चाहता है तो अमेरिका को भी।

चिंतन-मनन

राष्ट्रीय एकता में बाधक तत्व

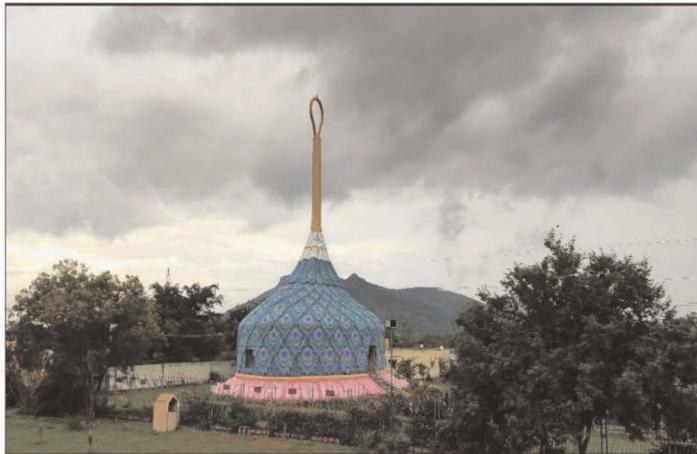
आर्थिक और सामाजिक असमानता राष्ट्रीय एकता में बहुत बड़ी बाधा है। उस असमानता का मूल है अहं और स्वार्थ। इसलिए राष्ट्र की भावात्मक एकता के लिए अहं-विसर्जन और स्वार्थ-विसर्जन को मैं बहुत महत्व देता हूँ। जातीय असमानता भी राष्ट्रीय एकता का बहुत बड़ा विघ्न है। उसका भी मूल कारण अहं ही है। दूसरों से अपने को बड़ा मानने में अहं पुष्ट होता है और आदमी अपने-आप में संतोष का अनुभव करता है। अहं का विसर्जन किए बिना जातीय भेद का अंत नहीं हो सकता। मनुष्य जन्मानु मनुष्य का शत्रु नहीं है। एक पेड़ की दो शाखाएं परस्पर विरोधी कैसे हो सकती हैं? फिर भी यह कहा जाता है कि धर्म-संप्रदाय मनुष्यों में मैत्री स्थापित करने के लिए प्रचलित हुए हैं। उनमें जन्मानु शत्रुता नहीं है, फिर मैत्री स्थापित करने की क्या आवश्यकता हुई? मैं फिर इस विश्वास को दोहराना चाहता हूँ कि मनुष्य-मनुष्य में स्वभावतः शत्रुता नहीं है। वह निहित स्वार्थ वाले लोगों द्वारा उत्पन्न की जाती है। उसे मिटाने का काम धर्म-संप्रदाय ने प्रारंभ किया, किंतु आगे चलकर वे स्वयं निहित स्वार्थ वाले लोगों से घिर गए और मनुष्य का मनुष्य का शत्रु मानने के सिद्धांत की पुष्टि में लग गए। इस चिंतन के आधार पर मुझे लगता है कि सांप्रदायिक समस्या का मूल भी अहं और स्वार्थ को छोड़कर अन्यत्र नहीं खोजा जा सकता। इसलिए सांप्रदायिक वैमनस्य की समस्या को सुलझाने के लिए भी अहं और स्वार्थ का विसर्जन बहुत आवश्यक है। भाषा, जो दूसरों तक अपने विचारों को पहुंचाने का माध्यम है, को भी राष्ट्रीय एकता के सामने समस्या बनाकर खड़ा कर दिया जाता है। अपनी भाषा के प्रति आकर्षण होना अस्वाभाविक नहीं है। पर हमें इस तथ्य को नहीं भुला देना चाहिए कि मातृभाषा के प्रति जितना हमारा आकर्षण होता है, उतना ही दूसरों को अपने मातृभाषा के प्रति होता है। इसलिए भाषाई अर्थाविशेष में फंरना कैसे तर्कसंगत हो सकता है। राष्ट्रीय एकता के लिए इन विषयों पर गंभीर चिंतन करना आवश्यक है।



विनोद कुमार सिंह

धन्य - धन्य है वह धरा, जहाँ अनगिनत संत-महापुरुष, ऋषि-मुनि और स्वयं भगवान के अवतार राम, कृष्ण, कबीर, तुलसी, नानक, बुद्ध और महावीर अवतरित होकर संपूर्ण सृष्टि और मानवता के कल्याण हेतु अमूल्य संदेश देते आए हैं। आज इसी कारण भारत को विविधता में एकता का प्रतीक माना जाता है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि सभी धर्मों के लोग भाईचारे के साथ शताब्दियों से एक साथ रहते आए हैं। इन्होंने संत परंपराओं में हजारों वर्ष पूर्व भगवान महावीर ने संपूर्ण संसार को शांति, मैत्री और मानवता का उपदेश दिया। इन्होंने 'अहिंसा परमो धर्म' का शाश्वत संदेश दिया-जो आज भी संसार के लिए प्रासंगिक है। विगत दिनों मुझे रेलवे बोर्ड के दिलीप कुमार, ई.आई.डी.पी. के कुशल नेतृत्व में नेशनल मीडिया टीम के सदस्य के रूप में तीन दिवसीय यात्रा पर आईटी नगर, बेंगलुरु जाने का स्वर्णिम अवसर मिला। संयोग से यह यात्रा सावन पूर्णिमा, रक्षाबंधन के पावन पर्व पर आरंभ हुई। ब्रिटीश के बीच हम दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे और हवाई मार्ग से

मंदारगिरी पर्वत व महावीर का शांति संदेश का स्वर्णिम अवसर



बेंगलुरु पहुंचे तो शाम हो चुकी थी। वहाँ रेलवे के स्थानीय पीआर टीम ने हमारा हार्दिक स्वागत किया और कारों के कार्फिले में हमें गंतव्य तक पहुंचाया रास्ते में हमने दक्षिण भारतीय व्यंजनों और स्पेशल कॉफी का आनंद लिया। अगले दिन के कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए जल्दी विश्राम किया। अगली सुबह प्रधानमंत्री द्वारा तीन वंदे भारत एक्सप्रेस और मेट्रो परियोजनाओं के उद्घाटन का मीडिया कवरेज किया। थकान के बावजूद हमारे टीम कुशल व कुशाग्र कप्तान दिलीप सर ने मुस्कुराते हुए

कहा - 'आप सभी अभी से थक गए? अभी तो हमें दर्शनीय स्थलों का आनंद लेना है।' हम सभी तैयार हो गए और कारों में एक रमणीय स्थल की ओर बढ़ा। रास्ते में हमने सुंदर मंदिरों, प्राचीन शिल्पकृतियों और जीवंत कला कृतियों की आकृतिक को पथरों में देखा। वहाँ से हम मंदारगिरी पर्वत की ओर बढ़े रास्ते में मैंने दिलीप सर से पूछा - 'हमारे ऋषि-मुनि, संत और देवी-देवता हमेशा कठिन पर्वतों और कंदराओं को अपनी तपोस्थली क्यों बनाते थे?' सर मुस्कुराए और बोले - 'ताकि हम जैसे लोग उनकी साधना में

व्यवधान न डालें। जब हम कठिनाई सहकर ऐसे स्थानों तक पहुंचते हैं, तभी हम उनके आशीर्वाद और दिव्यता का सही अनुभव कर पाते हैं।' मंदारगिरी पर्वत पर पहुंचकर हमने पिंजी आकार के 81 फुट ऊंचे गुरु मंदिर का दर्शन किया। यह मंदिर दिगंबर जैन तपस्वी श्री शांतिसागर जी महाराज को समर्पित है। पास ही चंद्रनाथ तीर्थंकर की भव्य प्रतिमा है, जो बाहुबली जैसी प्रतीत होती है। वहाँ हमने एक अद्भुत दृश्य देखा - गाय और शेरनी एक घाट पर जल पी रहे थे, गाय का दूध शेरनी का शकट पी रहा था वही शेरनी का दूध गाय का बछड़ा। यह दृश्य भगवान महावीर के अहिंसा और सह-अस्तित्व के संदेश का जीवंत प्रमाण प्रतीत हो रहा था। पर्वत की चोटी तक पहुंचने के लिए लगभग 460 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। शिखर पर चार प्राचीन जैन मंदिर हैं, जिनमें से दो चंद्रनाथ और दो पाश्र्वनाथ को समर्पित हैं। वहाँ की स्वच्छता, शांति और सुंदरता मन को मोह लेने वाली है। मंदिर परिसर के पीछे एक सुरम्य झील है, जो इस स्थल की आध्यात्मिकता को और भी गहरा कर देती है। बहलकी फुहारें, पहाड़ी की मनोहारी, हरियाली और वातावरण में व्याप्त शांति-यह सब मिलकर ऐसा अनुभव कराते हैं। मानो भगवान महावीर का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो रहा हो। वास्तव में अंत में हमने स्थानीय रेस्टोरेंट में स्वादिष्ट भोजन का आनंद लिया और वापस बेंगलुरु लौट आए। हमारे लिए यह यात्रा केवल एक आध्यात्मिक अनुभव नहीं, बल्कि जीवन के मूल्यों, शांति, सह-अस्तित्व और परिश्रम के महत्व की गहरी सीख भी दे गई।

डॉक्टरों के पचे: लिखावट पर अदालत की फटकार



बल्कि सामाजिक भी है। ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों में अक्सर मरीज कम पढ़े-लिखे होते हैं। जब वे डॉक्टर की पची लेकर दवा की दुकान पर पहुंचते हैं तो उनकी समझ से बाहर होता है कि कौन-सी दवा कितनी बार लेनी है। कई बार दवा विक्रेता भी लिखावट को गलत समझ लेता है। इससे मरीज गलत समय पर दवा खा लेता है, डोज विगड़ जाती है और बीमारी बढ़ जाती है। यह समस्या गंभवर्ती महिलाओं, बच्चों और जुजुर्ग मरीजों में और भी गंभीर हो जाती है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 हर नागरिक को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। अदालत ने सही कहा कि मरीज को अपनी बीमारी और इलाज की जानकारी मिलना उसका मौलिक अधिकार है। यदि प्रिस्क्रिप्शन ही अस्पष्ट और अधूरी जानकारी वाला हो तो यह अधिकार स्वतः ही बाधित होता है। इस संदर्भ में यह आदेश केवल चिकित्सा पद्धति के

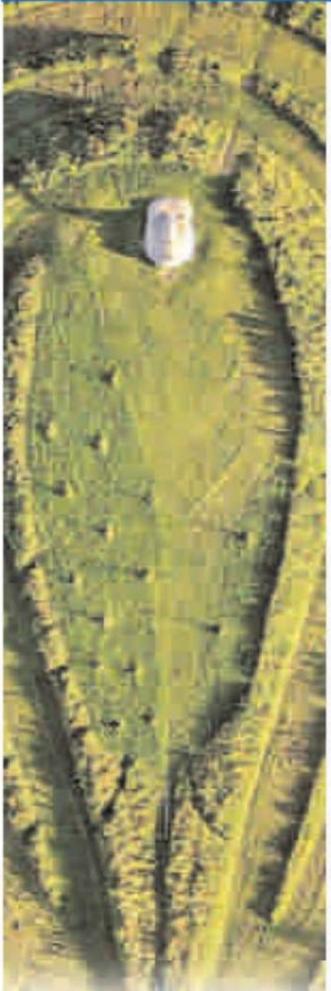
तकनीकी सुधार तक सीमित नहीं है, बल्कि यह नागरिक अधिकारों के संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। न्यायालय ने अपने आदेश में यह भी कहा कि जब तक देशभर में ई-प्रिस्क्रिप्शन (कंप्यूटर से बनी पची) की व्यवस्था पूरी तरह लागू नहीं हो जाती, तब तक सभी डॉक्टर कैपिटल लेटर्स में लिखें। यह सुझाव व्यावहारिक भी है और भविष्य की दिशा भी तय करता है। डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड और ई-प्रिस्क्रिप्शन के कई लाभ हैं मरीज का पूरा मेडिकल इतिहास सुरक्षित रहता है, फार्मासिस्ट को गलतफहमी की गुंजाइश नहीं रहती, दवा कंपनियों और हेल्थ इंश्योरेंस तक पारदर्शिता सुनिश्चित होती है और मरीज चाहे गांव का हो या महानगर का, उसे स्पष्ट जानकारी मिलती है। हाईकोर्ट ने नेशनल मेडिकल कमीशन (एनएमसी) को भी निर्देश दिया है कि मेडिकल कॉलेजों में छात्रों को साफ-सुथरी लिखावट और स्पष्ट प्रिस्क्रिप्शन की ट्रेनिंग दी जाए। यदि मेडिकल शिक्षा के शुरूआती दौर से ही

छात्रों को साफ लिखने और स्पष्ट पची देने का आदत डाल दी जाए, तो आने वाले वर्षों में यह समस्या स्वतः ही खत्म हो सकती है। यह सुधार मेडिकल एथिक्स का हिस्सा बनना चाहिए। अदालत ने राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को भी नीति बनाने का निर्देश दिया है। इस नीति के तहत छोटे क्लिनिक और ग्रामीण डॉक्टरों को कंप्यूटर आधारित प्रिस्क्रिप्शन सिस्टम के लिए आर्थिक सहायता दी जा सकती है। जिला स्तर पर सिविल सर्जन की निगरानी में जागरूकता बैठकों का आयोजन किया जाए और स्वास्थ्य विभाग समय-समय पर निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करे कि डॉक्टर पची पढ़ने योग्य लिख रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय अनुभव बताते हैं कि प्रिस्क्रिप्शन की स्पष्टता स्वास्थ्य सेवाओं में क्रांतिकारी सुधार लाती है। पश्चिमी देशों में डॉक्टरों द्वारा हाथ से लिखे पचे अब लाम्भग अतीत की बात हो चुके हैं। अमेरिका, यूरोप और जापान में ज्यादातर अस्पतालों और क्लिनिकों में ई-प्रिस्क्रिप्शन ही मानक बन चुका है। भारत में भी हाईडिजिटल इंडिया मिशन और हायब्रुभूम भारत डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड को बढ़ावा दिया जा रहा है। हाईकोर्ट का आदेश इन पहल को और गति देगा। हालांकि चुनौतियां कम नहीं हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली और इंटरनेट की कमी से डिजिटल व्यवस्था लागू करना कठिन होगा। छोटे क्लिनिकों के लिए कंप्यूटर, प्रिंटर और सॉफ्टवेयर की लागत बड़ी बाधा है। डॉक्टरों पर पहले से ही प्रशासनिक बोझ है, ऐसे में अतिरिक्त प्रशिक्षण और औपचारिकताएं असुविधा पैदा कर सकती हैं। यह भी सही है कि मरीजों की भाषा और समझ अलग-अलग होती है। अतः केवल अंग्रेजी या कैपिटल लेटर्स काफी नहीं होंगे, बल्कि स्थानीय भाषा में भी स्पष्टता जरूरी है। डॉक्टरों की लिखावट अब केवल मजाक या व्यंग्य का विषय नहीं रह गई, बल्कि यह सीधे-सीधे जीवन और मृत्यु का प्रश्न है।



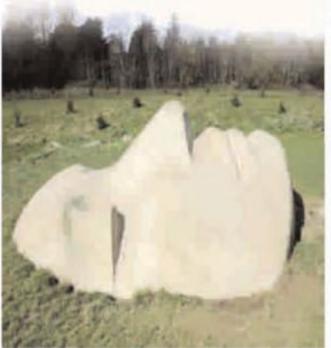
डॉ. सत्यवान सौरभ

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में एक ऐसा आदेश दिया है, जो न केवल हरियाणा-पंजाब बल्कि देश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर गहरी छाप छोड़ेगा। अदालत ने स्पष्ट कहा कि डॉक्टरों को अब मरीजों की पची साफ लिखनी होगी। बेहतर होगा कि डॉक्टर अपनी लिखावट कैपिटल लेटर्स में करें या फिर टाइप/डिजिटल रूप में पची दें। यह फैसला सिर्फ लिखावट की औपचारिकता तक सीमित नहीं है। यह बल्कि यह सीधे मरीज की सुरक्षा और जीवन के अधिकार (अनुच्छेद 21) से जुड़ा हुआ है। भारत में अक्सर यह शिकायत सुनने को मिलती रही है कि डॉक्टरों की लिखावट इतनी उलझी होती है कि फार्मासिस्ट या मरीज को समझ ही नहीं आता कि कौन-सी दवा, कितनी मात्रा में और कितने समय तक लेनी है। ऐसे में गलत दवा या गलत खुराक से मरीज की हालत विगड़ जाना आम बात है। कई बार तो यह लापरवाही मोत तक का कारण बन चुकी है। यह स्थिति केवल छोटे शहरों या ग्रामीण इलाकों तक सीमित नहीं है। बड़े-बड़े कॉर्पोरेट अस्पतालों में भी प्रिस्क्रिप्शन का यह संकट मौजूद है। लिहाजा हाईकोर्ट का हस्तक्षेप एक जीवन रक्षक पहल के रूप में देखा जाना चाहिए। यह विषय केवल चिकित्सीय नहीं



रोमांच से भरी ये कलाकृति बनी आयरलैंड की पहचान

आयरलैंड के शहर डबलिन में मैरले नाम का एक पार्क है। इस सार्वजनिक पार्क में बना यह चेहरा विश्वप्रसिद्ध ब्रिटिश इतिहासकार और पुरातत्वविद एग्नेस कान्वे का है। इसे बनाया भी एग्नेस ने ही है। एग्नेस ने सेलेशटियल पहाड़ के बारे में सुना था। उन्होंने उसके बारे में खूब खोजा लेकिन सटीक जानकारी नहीं जुटा पाई। एग्नेस सिर्फ अपने ख्यालों में ही उस जादुई पहाड़ की यात्रा कर पाई। अपनी कल्पनाओं को उन्होंने डबलिन के इस पार्क में उकेर दिया। आकृति को नाम भी दिया ड्रीमिंग आबाउट द सेलेशटियल माउंटन। अब आयरलैंड आने वाले पर्यटक एग्नेस की कल्पनाओं को देखने चले जाते हैं। चीन स्थित सेलेशटियल माउंटन अब तियान शान नाम से जाना जाता है।



500 साल पुराना वो गांव जहां दो देशों के बीच दुनिया का हुआ था बंटवारा!

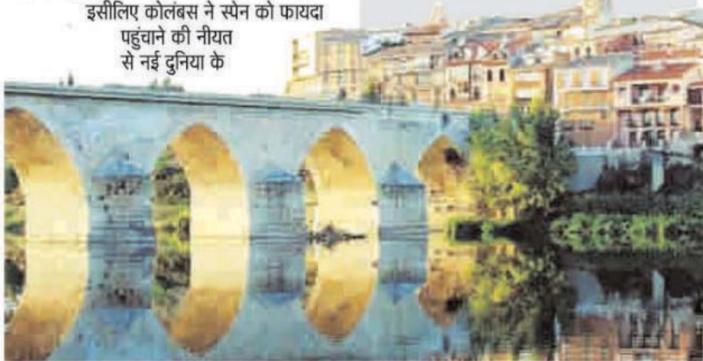
एक जमाना था जब दुनिया के एक बड़े हिस्से पर अंग्रेजों का राज था। कहा जाता था कि ब्रिटिश साम्राज्य में सुरज नहीं अस्त होता। मगर, उस दौर में भी दुनिया का एक बड़ा हिस्सा ऐसा था, जहां अंग्रेजों का नहीं, दूसरे यूरोपीय देशों का राज था। मध्यकाल में यूरोपीय देश स्पेन का दुनिया के एक बड़े हिस्से पर राज हुआ करता था। खास तौर से अमेरिकी महाद्वीप पर।

आज के अमेरिका और कनाडा को छोड़ दें तो, बाकी अमेरिकी महाद्वीप पर स्पेन का ही राज था। कम्बोवेश पूरे के पूरे दक्षिण अमेरिका में स्पेनिश ही बोली जाती है, सिवा एक देश के और इस देश का नाम है ब्राजील। सवाल ये है कि ऐसा क्यों था? जब पूरा का पूरा दक्षिण अमेरिका स्पेनिश बोलता है, तो ब्राजील में पुर्तगाली क्यों बोली जाती है? लैटिन अमेरिका में ब्राजील ऐसा देश है, जो पुर्तगाल का उपनिवेश था। बाकी दक्षिणी अमेरिका, स्पेन के साम्राज्य का हिस्सा था। ब्राजील और बाकी अमेरिका की किस्मत का फैसला एक छोटे से गांव में हुआ था। ये गांव आज के स्पेन के ब्लाडोलीड सुबे में पड़ता है। इस गांव का नाम है टॉर्डेसियास। यहीं पर 1494 में स्पेन और पुर्तगाल के बीच समझौता हुआ था। जिसके तहत दोनों देशों ने नई दुनिया को आपस में बांटा था। ये नई दुनिया आज के अमेरिकी महाद्वीप थे। इनकी तलाश इटली के नाविक क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। हालांकि कोलंबस, भारत की तलाश में स्पेन के खर्च पर रवाना हुए थे, मगर वो पहुंच गए अमेरिका। स्पेन का दक्षिण अमेरिका से नाता टॉर्डेसियास आज गांव नहीं बल्कि छोटा सा शहर बन गया है। ये झुररो नदी के किनारे स्थित है। बेहद औसत दर्जे का ये शहर नई और पुरानी विरासतों का मेल है। यहां पुराने जमाने की कई इमारतें हैं। भले ही स्पेन में इस शहर को लोग न जानते हों, मगर लैटिन अमेरिका में बहुत से लोगों को इस शहर के बारे में पता है। इतिहासकार बताते हैं कि ये शहर मध्य काल में छोटा सा गांव था। इसके आस-पास से कई अहम रास्ते गुजरते थे, इसी वजह से पुर्तगाल और स्पेन के राजाओं ने इस जगह को इतने अहम समझौते के लिए चुना। यहां पर पुराने राजमहल और दूसरी शानदार इमारतें भी थीं। ये भी समझौते के लिए इस कस्बे को चुनने की बड़ी वजह थी। पंद्रहवीं सदी के आखिर में आज का स्पेन किंगडम ऑफ कस्टील के नाम से जाना जाता था। इसके एक हिस्से पर अरागॉन सल्तनत थी। वहीं पड़ोस में पुर्तगाल स्थित था। जब कोलंबस अमेरिका का पहला सफर करके लौट रहे थे, तो समुद्री तूफान की वजह से कोलंबस को अपने जहाज पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में रोकने पड़े। मजबूरन कोलंबस को नई दुनिया की अपनी खोज के बारे में पुर्तगाल के राजा जॉन द्वितीय को बताना पड़ा।

पुर्तगाल और स्पेन के बीच 1479 में पोप की



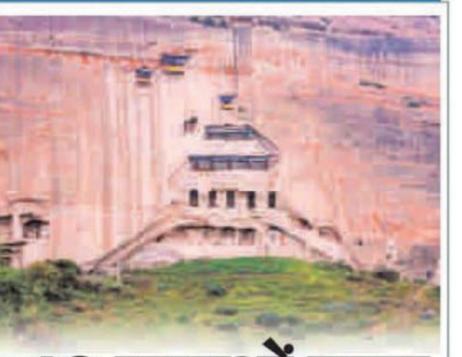
मध्यस्थता से एक समझौता हुआ था। इसके तहत जॉन द्वितीय को लगा कि नई दुनिया जिसे कोलंबस ने खोजा है, वो उसके अधिकार क्षेत्र में आती है। उसने फौरन उसे अपना इलाका घोषित कर दिया। इसी दौरान कोलंबस के साथ गए नाविक मार्टिन अलोसो पिन्जोन ने नई दुनिया की खोज की खबर स्पेन तक पहुंचा दी। इसके बाद स्पेन के राजा फर्डिनेंड और महारानी इजाबेला ने अपने हकदार पोप के पास दौड़ा। पोप ने अपने आदेश के तहत अटलांटिक के आर-पार एक लाइन खींची और कहा कि इसके पूरब का हिस्सा पुर्तगाल का होगा और पश्चिमी हिस्से पर स्पेन का राज होगा। असल में पोप अलेक्जेंडर षष्ठम, स्पेन के ही रहने वाले थे। इसीलिए उन्होंने स्पेन के हक में ये फरमान जारी कर दिया। इससे नाराज पुर्तगाल ने स्पेन के खिलाफ जंग की तैयारी शुरू कर दी। पुर्तगालियों को अपने अफ्रीकी उपनिवेशों और अटलांटिक महासागर स्थित अपने जजीरों की फिक्र थी। लेकिन जिस तरह पोप ने अटलांटिक महासागर में लाइन खींचकर बंटवारा किया था, उससे तो पुर्तगाल के अफ्रीका जाने के रास्ते भी मुश्किल में पड़ते दिख रहे थे। इसीलिए पुर्तगाल ने स्पेन के खिलाफ जंग की तैयारी शुरू कर दी। उस वक्त स्पेन को मालूम था कि वो समुद्री जंग में पुर्तगाल से नहीं जीत सकता। इसीलिए उसने सुलह का रास्ता अपनाया। इसी दौरान कोलंबस अमेरिका के अपने दूसरे सफर पर रवाना हो गए। वहां उन्होंने दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप की खोज की, लेकिन उसका गलत नक्शा बनाकर स्पेन और पुर्तगाल को खबर की। कोलंबस को नहीं मालूम था कि जॉन ने पोप के नए फरमान को कम्बोवेश मान लिया था। इसीलिए कोलंबस ने स्पेन को फायदा पहुंचाने की नीयत से नई दुनिया के



नक्शे में झूठे हेर-फेर करके खबर की। नतीजा ये हुआ कि ब्राजील का पूर्वी तट पुर्तगाल के हिस्से में आया। स्पेन के राजा फर्डिनेंड और महारानी इजाबेला भी इस बात पर राजी हो गए, क्योंकि उन्हें मालूम ही नहीं था कि जिस लाइन को वो पुर्तगाल के साथ मान रहे हैं, उसके पार भी कोई जमीन है। इसी गलत नक्शे की बुनियाद पर पुर्तगाल और स्पेन के बीच सन 1494 में टॉर्डेसियास का समझौता हुआ। लेकिन सन 1500 में पुर्तगाली नाविक पेड्रो अल्वारेज ब्राजील के तट पर जा पहुंचे। उन्होंने इस पर अपने देश के राजा का हक बताया। बाद के कुछ बरसों के भीतर पुर्तगाल ने दक्षिण अमेरिका के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। पुर्तगाल के हिस्से वाला हिस्सा कम्बोवेश आज का ब्राजील है। यही वजह है कि जहां ज्यादातर दक्षिण अमेरिकी देशों में स्पेनिश बोली जाती है, वहीं ब्राजील में पुर्तगाली जमान बोली जाती है। और इसकी ऐतिहासिक वजह स्पेन का टॉर्डेसियास शहर है, जो आज से पांच सौ साल पहले एक गांव हुआ करता था और इसी गांव में पुर्तगाल और स्पेन के बीच नई दुनिया का बंटवारा हुआ था।

टोर्डेसियास की संधि क्या थी?

टॉर्डेसियास की संधि स्पेन और पुर्तगाल के राज्यों के बीच यूरोप के बाहर की भूमि की खोज और विजय के अधिकारों के बारे में एक समझौता था। दुनिया को अटलांटिक महासागर में स्थित एक उत्तर-दक्षिण रेखा द्वारा विभाजित किया गया था, जो उत्तर-पश्चिमी अफ्रीकी तट से दूर पुर्तगाली-नियंत्रित केप वर्ड द्वीप समूह के पश्चिम में 370 लीग (लगभग 1100 मील) दूर है। इस समझौते के तहत, स्पेन रेखा के पश्चिम में सभी गैर-ईसाई भूमि पर स्वामित्व का दावा कर सकता था, और पुर्तगाल अकेले रेखा के पूर्व में सभी गैर-ईसाई भूमि पर दावा कर सकता था। पोप अलेक्जेंडर VI ने 1494 में इस समझौते की मध्यस्थता की थी, ताकि अफ्रीकी तट और नई दुनिया के अन्वेषणों के परिणामस्वरूप प्रतिद्वंद्वी राज्यों के बीच उत्पन्न विवादों को सुलझाया जा सके। दो इबेरियन राज्यों को निर्देश दिया गया था कि वे अपने सामने आने वाले गैर-ईसाइयों को रोमन कैथोलिक धर्म में परिवर्तित करें और जो लोग इसके अधीन नहीं होंगे, उन्हें गुलाम बनाने का अधिकार दिया गया।



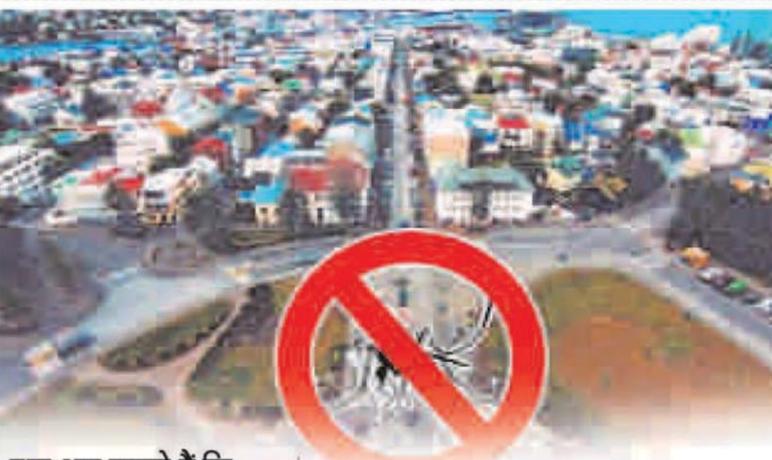
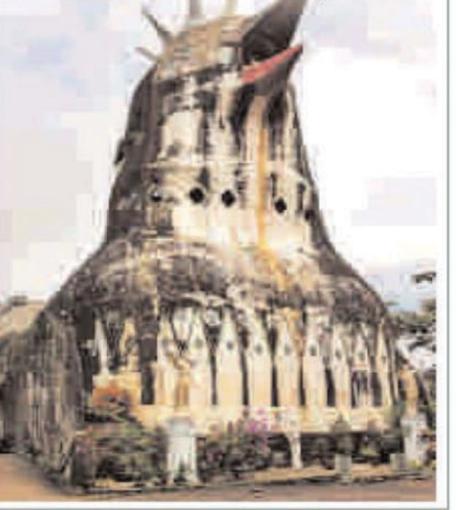
40 गुफाओं वाला चीन का मंदिर

चीन के झांगए गांसु में 1600 साल पुराने स्थित हॉसंशू मंदिर की गिनती चीन के ऐतिहासिक स्थलों में की जाती है। ये मंदिर तीन चीनी पारंपरिक धर्म बौद्ध, कन्फ्यूशियस और ताओ के मिलाप के लिए बनाया गया है। चाइनीज आर्किटेक्चर का अध्ययन करने वाले लोगों के लिए ये एक प्रमुख केन्द्र है। इस मंदिर की खासियत ये है कि यहां पर चालीस अलग अलग गुफाएं हैं, जो दूसरे से जुड़ी हुई हैं। इस अनोखे प्रकार के मंदिर को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं।



इंडोनेशिया का ये चर्च अपने आकार से करता है सबको हैरान

इंडोनेशिया के जंगलों में बना ये चर्च अपनी आकृति के चलते लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। घने जंगलों के बीच मौजूद इस चर्च का निर्माण डेनियल आलम्सजाह ने करवाया था। हालांकि इसे धर्म के लोगों की साधना के केन्द्र के तौर पर बनाया गया था। मगर इसका मकसद पूर्ण नहीं हो सका। एक चिकेन के आकार में तैयार किए गए इस चर्च की आकृति हर तरफ से एक पक्षी की भांति दिखती है। इस चर्च को सन् 1990 में जावा द्वीप पर मेगेलंग जंगल में उंची पहाड़ी पर बनाया गया था। मगर आर्थिक संकट के चलते चर्च का निर्माण पूरा नहीं हो पाया था। मानव रचनात्मकता के इस बेजोड़ नमूने को देखने के लिए लोग दूर दूर से यहां आते हैं। डेनियल आलम्सजाह का कहना है कि उन्होंने सपने में भगवान को देखा, जिन्होंने उसे पक्षी के आकार का धार्मिक स्थान बनवाने का आदेश दिया था, जो किसी उंची पहाड़ी पर स्थापित हो। उसके बाद उन्होंने चर्च बनाने का काम शुरू कर दिया था।



वया आप जानते हैं कि दुनिया में ऐसे भी कुछ देश हैं, जहां इस छोटे से मच्छर का नामोनिशान तक नहीं है। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ देशों के बारे में -



न्यू कैलेडोनिया

कई द्वीपों की चेन को मिलाकर बना न्यू कैलेडोनिया दुनिया का सबसे लंबा आइलैंड है। चारों ओर फैला नीला समुद्र, केरल रीफ और दूर-दूर तक फैली सफेदी मन को लुभा देती है। यहां ऐसे बहुत से पौधे और जानवर मिलते हैं, जो बहुत कम पाए जाते हैं। यहां का तापमान हमेशा इतना गर्म बना रहता है कि साल भर आराम से सिर्फ टी-शर्ट पहनकर रहा जा सकता है। यह ट्रिस्ट का पसंदीदा जगह है। यहां बड़ी तादाद में ट्रिस्ट आते हैं। इसके

ऐसे देश, जहां नहीं है मच्छर का नामोनिशान

अलावा यह जगह स्कूबा डाइविंग सीखने के लिए एक बेस्ट प्लेस है और साल भर यहां लोग स्कूबा डाइविंग सीखने आते रहते हैं।

आइसलैंड

हरी-भरी वादियों, ग्लेशियर और हजारों किमी लंबे समुद्र तट वाला यह देश काफी खूबसूरत है। यह अपने गर्म झरनों (ज्वालामुखी के कारण) के लिए भी मशहूर है। इसे कल्चर और आर्ट का सेंटर माना जाता है। यहां की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और यहां कई ऐसे ज्वालामुखी हैं, जो यूरोप के एयर ट्रैफिक में रुकावट पैदा कर सकती हैं। यह काफी ठंडा देश है और सर्दियों में यहां बहुत सौफॉल होता है, जिसकी वजह से यहां मच्छर नहीं पनप पाते हैं।

फेंच पॉलिनेशिया

साउथ पैसिफिक में स्थित द्वीपों का यह समूह दुनिया के कुछ सबसे अलग-थलग वाले इलाकों में से एक है। यहां का सबसे पॉपुलर आइलैंड ताहिती है। यहां की कुल आबादी करीब ढाई लाख से अधिक है। आधिकारिक भाषा फेंच है और ट्रिज्म रोजगार का सबसे बड़ा जरिया है। यहां कुछ ऐसे बड़े-बड़े केकड़े पाए जाते हैं, जो नारियल को भी तोड़ सकते हैं। इसलिए थोड़ा सावधान रहना जरूरी है। इसकी खासियत ये है कि यहां मच्छरों की संख्या न के बराबर है।



आइसलैंड की पीली नदी में देखने को मिलता है अद्भुत नज़ारा

प्रकृति कितनी रंगबिरंगी है, आइसलैंड की पीली नदी से पता चलता है। आइलैंड की पीली नदी का नज़ारा बड़ा अद्भुत है।

इस नदी को थजोर्स रिवर के नाम से भी पहचाना जाता है। इस जगह पर पीली नदी के साथ आपको नीला समुद्र, हरे-भरे मैदान और काली रेत वाले बीच दिख जाएंगे। यानी एक ही जगह पर एक साथ इन रंगों का नज़ारा देखने को मिल सकता है। यह खूबसूरत नज़ारा दक्षिण के होफ और दक्षिण-पूर्व में स्थित कलकाफेल टाउन के बीच के इलाके में देखने को मिलता है। यह पीली नदी आइसलैंड की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। इस नदी की लंबाई 5.464 किमी है।

On BJP worker's complaint, Chhattisgarh cops book TMC's Mahua Moitra over remarks on Amit Shah

NEW DELHI: Chhattisgarh Police Saturday booked Trinamool Congress (TMC) Lok Sabha MP Mahua Moitra for her remarks aimed at Union Home Minister Amit Shah.

The FIR was filed at the Mana Camp police station in the Raipur police district based on a complaint from a local worker of the ruling Bharatiya Janata Party (BJP), who alleged that for the first time, a Member of Parliament, had 'threatened' a home minister. Based on the complaint from BJP worker Gopal Samanto, Raipur district police booked Moitra, the Lok Sabha MP from Krishnanagar in West Bengal, under sections 196 and 197 of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023.

Section 196 outlines the punishment for offences that promote enmity between different groups on grounds of religion, race, place of birth, residence, language, etc., and for acts prejudicial to the maintenance of harmony. Section 197 deals with offences such as imputations and assertions prejudicial to national integration. Speaking at the press Thursday in West Bengal's Nadia, Moitra had questioned the ruling BJP on the issue of infiltration, stating that the onus to curb cross-border infiltra-



tion is on the Ministry of Home Affairs (MHA), under Shah. She said Prime Minister Narendra Modi gave out a call against cross-border infiltration in his Independence Day address from the ramparts of the Red Fort while Shah was standing in the first row and clapping. "If we don't have anyone to protect our borders, if citizens of another country infiltrate in huge numbers every single day, and if our citizens complain that they are seeing our mothers and sisters in a bad light and the infiltrators are snatching their lands—then the first thing you should do is cut Amit Shah's head and put it on your table," she said.

Adding, in Bangla, "When the home ministry and home minister can't protect the borders of the nation, Prime Minister him-

self is saying infiltrators are looking at our mothers and sisters in a bad light and taking away our lands, who is at fault? The fault is ours or yours?"

Two days later, BJP's Samanto approached the police, alleging Moitra had challenged the federal structure of the country and that her statement could spur hatred towards the Bengali community in the country.

"This is the first time that an MP elected to the country's highest body, Parliament, has given such a statement related to loss of life against the country's Home Minister. This is a warning to all peace-loving citizens that whoever talks about Bangladeshi infiltration will have to pay the price of their life. Sir, in this letter, I would also like to mention that I myself come from the Bengal

community and am proud of the fact that our society has made an exceptional contribution in the country's freedom struggle, art, literature and science, etc. and due to which our society is receiving special love and respect in the entire region," Samanto alleged in the complaint which formed the basis of the FIR. "Due to this statement of Mahua Moitra, there is a fear that hatred will arise among the people towards the Bengali community and in future, criminal incidents against the people of the Bengali community may also increase. Therefore, by immediately bringing such individuals before the law of the country, they should be prevented from putting the lives of lakhs of people at risk for their own political gain. This is also an open challenge to the Constitution of the country where a democratically elected MP is talking about damaging the federal structure of the country," he alleged. ThePrint reached Moitra for comment via calls and text but had not received any response by the time of publication. This report will be updated if and when a response is received. Moitra had in a post on X on 29 August termed these developments a campaign against her by the "BJP troll cell".

Grasslands in Assam's Manas National Park shrink by 50 pc in three decades

GUWAHATI: Grasslands in Assam's Manas National Park and Tiger Reserve have shrunk by nearly 50 per cent in the last three decades due to various factors, including climate change, officials said. Manas National Park (MNP) and Tiger Reserve Field Director C Ramesh told PTI that grasslands paving the way for woodlands is a natural process that takes over 100 years but it has accelerated in the UNESCO World Heritage Site, forcing herbivorous animals to get concentrated in areas where grasses are available.

"We are witnessing that the grassland expanse is shrinking and woodlands are increasing. That's a part of succession, but it is happening very rapidly, and that is a cause of concern for us as grasslands are crucial for the ecosystem," he said.

"As per our records, we have lost almost 50-60 per cent of our grasslands in the last 30-35 years," he added. Ramesh stated that the trees and shrubs that are replacing grasslands are of native species. With woodlands replacing the grasslands, animals are getting concentrated in areas that have grass.

"Non-territorial animals such as deer roam around the park to feed on grass. Now, they are getting concentrated in available grasslands," Ramesh said. The grasslands of the nation-



park are unique from a biodiversity point of view as it is the only place in the world where greater one-horned rhino, swamp deer, hog deer, pygmy hog, hispid hare, wild buffalo, Bengal florican, tiger and elephant co-exist in the same habitat.

Speaking about the crisis, eminent conservationist and grassland expert Bibhuti Prasad Lahkar told PTI that the grasslands are affected in two ways — biotic and abiotic or anthropogenic.

"In the biotic process, a grassland gradually converts into scrubland with the spreading of invasive species, and becomes woodland by succession. Climate change accelerates the spread of invasive species," he added. The anthropogenic pattern means affecting the grassland through livestock graz-

ing, uncontrolled burning and grass cutting for various purposes. Lahkar said that the diversity of grasses has also been declining over the years. "Different animals depend on different types of grasses. So, if a particular species of grass decreases, then the animals dependent on that grass will also gradually vanish from the park," he added. Lahkar said that flood plays a key role in maintenance and management of the sub-Himalayan grassland to a large extent, but areas like MNP usually do not experience continuous flooding, and if it occurs, it typically lasts for only a few hours.

"Moreover, nowadays, we are seeing very erratic rainfall. This is gradually impacting the dynamics of the grassland, including changes in the soil composition," he added. Lahkar said very little emphasis is given in Assam as developing habitats as the primary focus is still on developing infrastructure and combating poaching. Echoing similar views, Gauhati University Assistant Professor (Environmental Science) Minakshi Bora said climate change is responsible for altering MNP's grassland community, enabling invasive species like Chromolaena odorata and Mikania micrantha to thrive. "These species outcompete native vegetation, reducing biodiversity and altering ecosystem processes. Effective conservation efforts are crucial to mitigate the impacts of invasive species and protect the park's unique biodiversity," she added. Bora said that rising temperatures and declining precipitation have disrupted the hydrological cycle in the Manas River Basin. "Data from recent studies indicate a gradual decline in the frequency of rainfall, resulting in reduced summer water flows and increased potential evapotranspiration. These factors lead to altered river discharge, frequent droughts and declining water quality, which are directly putting stress on the grassland ecosystems, which we know as the backbone of MNP," she added.

Rajasthan Assembly witnesses uproar; proceedings adjourned till Wednesday

JAIPUR: The Monsoon session of the Rajasthan Assembly began on a stormy note on Monday as Congress and BJP members raised slogans against each other, prompting Speaker Vasudev Devnani to adjourn proceedings till Wednesday.

Congress MLAs shouted slogans of "vote chor gadi chhodo" (vote thief, step down) and displayed placards inside the House. Despite repeated appeals for order by the Speaker, the Congress members remained defiant. The Speaker asked them to maintain decorum, saying this is not a marketplace or a street and members cannot behave like this in the Assembly.

"This is not a marketplace or a street corner. Maintain

the dignity of the House," Devnani said.

Targeting opposition benches, he also reminded the Leader of Opposition to uphold the dignity of the House and refrain from using inappropriate words.

BJP MLAs also raised slogans against Congress leader Rahul Gandhi, shouting "gaali baaz Rahul Gandhi". The BJP has been protesting against Gandhi for alleged abuses directed at Prime Minister Narendra Modi's mother during the Congress leader's 'Voter Adhikar Yatra' in poll-bound Bihar.

During the proceedings, Devnani informed the House that the Anta Assembly seat (Baran) had fallen vacant due to the conviction of Kanwar Lal Meena in a criminal case.

The report of the Select Committee on the coaching centre regulation bill was also tabled by Deputy Chief Minister and Committee Chairman Dr. Premchand Bairwa.

The speaker also read out a message from the Governor regarding the return of a bill. Earlier when the House met for the day, obituary references were made to former governors L Ganesan and Satpal Malik, former chief ministers Shibu Soren (Jharkhand), V.S. Achuthanandan (Kerala), Vijay Rupani (Gujarat); former MPs Girija Vyas and Colonel Sonaram, former MLAs Madan Kaur, Sohan Singh and Krishna Ram Nai.

After paying tributes to departed leaders, the House was adjourned till Wednesday.

day. Tuesday has been declared a holiday in view of Ramdev Jayanti.

Speaking to reporters outside the assembly, Leader of Opposition Tikaram Jolly charged that the BJP had rigged both the Lok Sabha and Assembly elections. He accused the Election Commission of being complicit and claimed that Congress had exposed its functioning.

Former deputy CM and Tonk MLA Sachin Pilot alleged that elections were repeatedly undermined through electoral malpractice. "Some people are trying to steal votes and repeatedly form governments through unfair means. The entire country is now speaking up against this and the Congress will not tolerate vote

theft," Pilot told reporters.

"Vote theft is not just happening in Bihar or Karnataka. It has been attempted in Haryana, Maharashtra and Rajasthan too. There must be a thorough investigation. Those sitting in the Election Commission in BJP's disguise must be removed," he demanded. Independent MLA Ravindra Singh Bhati entered the Assembly premises carrying posters demanding implementation of a Khejri tree protection law. "If the state government fails to act in time, I will strongly oppose it," Bhati told reporters.

Asked about the uproar in the House, government Chief Whip Jagdishwar Garg told reporters that the Congress has a record of using abusive language.

"It's Getting Late": Trump claims India "offered to cut tariffs to nothing"

NEW DELHI: US President Donald Trump claimed Monday that India has offered to reduce its tariffs on US goods to zero, underlining that New Delhi should have done it years ago.

The Trump administration has imposed 25 per cent reciprocal tariffs on India and an additional 25 per cent levies for Delhi's purchases of Russian oil, bringing the total duties imposed on India to 50 per cent, among the highest in the world. Trump has accused India of fueling Moscow's deadly attacks on Ukraine by purchasing Russian oil. However, he has refrained from tougher US sanctions on Russia itself. Defending India's oil purchase, External Affairs Minister



S Jaishankar argued that the same yardstick has not been applied to China and the European Union, the largest importer of Russian crude oil and Russian LNG, respectively.

"They have now offered to cut their tariffs to nothing, but it's getting late. They should have done so years

ago," Mr Trump posted on Truth Social, adding that the relationship between the two countries has been a "one-sided disaster". New Delhi said that, like any major economy, it will take all necessary measures to safeguard its national interests and economic security.

Stop more Maratha protestors from entering Mumbai: Bombay High Court directs State

NEW DELHI: In an urgent three-hour hearing on Monday (September 1, 2025), a Special Bench of Justices Ravindra V. Ghuge and Gautam A. Ankhad of the Bombay High Court directed the Maharashtra Government to clear protestors from Mumbai streets by Tuesday (September 2, 2025), 4 p.m. and prevent any more protestors from entering the city.

Taking cognisance of news reports and social media videos showing protestors climbing traffic signals, playing kabaddi and tug-of-war, bathing, urinating on streets, and damaging heritage property, the Court said the situation was "untenable" and needed immediate correction.



The Court said protestors must be restricted to Azad Maidan, the only venue where permission was granted for a one-day agitation. "There should be no protest anywhere else apart from Azad Maidan. The life of Mumbaiers should be normalised," the Bench observed. The State informed

the court that permission had been given to only 5,000 protestors for one day, but many more had gathered at other locations, including CSMT, Flora Fountain, and the State Secretariat.

The Court questioned why "unauthorised protestors" had not been sent back and instructed the Government

to stop further influx into Mumbai. The Bench also reminded the organisers to adhere to the August 26 order that restricted protest timings to 9 a.m. to 6 p.m. The State submitted that activist Manoj Jarange-Patil had refused to accept the Government's notice regarding violation of conditions. "There was no permission for a fast unto death. The organisers had the responsibility to follow the rules, but they have clearly flouted them. Mumbaiers should not be inconvenienced," the court observed.

The Bench also directed the State to monitor Mr. Jarange's health and ensure immediate medical assistance if required.

Why Jagdeep Dhankhar is at home in INLD chief Abhay Chautala's farmhouse

NEW DELHI: IT'S far from a surprise that Jagdeep Dhankhar, who has remained out of public view since he stopped down as former Vice-President more than a month ago, has picked Indian National Lok Dal (INLD) chief Abhay Singh Chautala's farmhouse in Delhi's Chhatarpur Enclave to stay in, as he waits for his official residence.

The ties between Dhankhar and the Chautalas go back nearly 40 years, to 1989, when Abhay's grandfather Devi Lal — Haryana's foremost Jat leader and then Chief Minister — identified the young lawyer from Rajasthan as a potential "leader". In turn, Dhankhar, also a Jat, always referred to Devi Lal as his "mentor".



Talking to The Indian Express ahead of Dhankhar moving into his farmhouse, Abhay said, "When I learnt Dhankhar ji was looking for a house to stay in and his own accommodation was not ready, I called him and asked him to stay at our place. It is a family gesture towards a person we see as our elder. I told him that he does not need to

look for any alternative accommodation, and that it is his own house and he should come here. He graciously accepted."

Dhankhar had caught Devi Lal's eye when he organised 500 vehicles from Rajasthan for an Opposition rally held on September 25, 1989, to mark Devi Lal's birthday, at Boat Club near India Gate.

Devi Lal was at the time one of the leading figures of the Opposition coalition that had come together to challenge the Rajiv Gandhi-led Congress government at the Centre, and the success of the Boat Club rally was a big step in that direction.

In the 1989 Lok Sabha elections, the Opposition coalition fought as the Janata Dal. Devi Lal offered Dhankhar the Janata Dal ticket from the Jhunjhunu Lok Sabha seat, and actively campaigned for him. Not only did it strengthen their bond but it also meant that when Devi Lal became the Deputy Prime Minister in the Janata Dal government that replaced the Congress, Dhankhar was catapulted to Union Minister of State (Parliamentary Affairs).

Bengaluru techie, 41, dies after being bitten by snake hiding in his footwear

NEW DELHI: A 41-year-old software engineer in Bengaluru died on Saturday after being bitten by a venomous snake that had slithered into his footwear. The victim has been identified as Manju Prakash, who was an employee of TCS and a resident of Ranganatha Layout. According to police reports and accounts from family members, Mr Prakash had left his Crocs slippers outside the front door of his home. After stepping out briefly to purchase juice from a nearby shop, he returned home and slipped his feet into the footwear, unaware that a snake had taken refuge inside one of the slippers during his absence. Mr Prakash had previously suffered an accident that resulted in a loss of sensation in his leg, a condition that prevented him from feeling the snakebite. Unaware, he took off his footwear and went inside his room to rest. A family worker later noticed a

snake inside the slipper and alerted his father, who carefully removed the reptile, which was found to be dead. A family member said the snake likely died of suffocation inside the Crocs. When Mr Prakash's mother went to check on him, she found him lying on the bed unresponsive, with foam around his mouth and a bleeding leg. The family immediately rushed him to a nearby private hospital, where doctors declared him dead. The shocking incident has raised concerns among residents about the presence of snakes in residential areas, particularly during monsoon seasons when such reptiles are known to seek shelter in homes and gardens. Experts have since urged residents to exercise caution, advising them to check footwear and dark corners of homes for snakes, especially in areas close to greenery or during rainy weather.

Flood alert in Delhi after 29,000 cusecs of water released from Hathnikund barrage

NEW DELHI: The Delhi government has issued a flood alert as the water level of the Yamuna River is expected to exceed the danger level after the release of 29,313 cusecs of water from Hathnikund Barrage on Monday morning.

Officials were instructed to maintain strict vigilance, along with patrolling in low-lying areas. "As the water level of ORB (Delhi Old Railway Bridge) may cross the danger level and is likely to exceed 206.50m, a CWC advisory may be expected soon. So, all the Sector Officers are hereby advised to keep a strict vigil in their respective areas and to take necessary action at vulnerable points, such as people residing within the river embankments, shall be warned and shifted to safer places," a Delhi government order said.

"The police and the staff of 1 & FC Department would undertake patrolling along right and left marginal embankments and keep vigil round the clock on the vulnerable points, regulators/

pumps, etc. as required," it added. On Thursday, a flood relief camp was set up in Delhi's Mayur Vihar, as the water level of the River Yamuna had crossed the danger mark the previous day.

"These tents are set up for people living near the river; they will come out and live in these tents when the flood comes," Ashok, a resident of Mayur Vihar, told ANI about these flood relief camps.

Meanwhile, IMD, on Sunday, said that India has recorded one of its highest rainfall levels in decades during August 2025, with exceptional showers across several states.

Addressing a virtual press conference in the national capital, IMD Director General Mrityunjay Mohapatra emphasised that monsoon activity revived strongly in the second half of the month and is expected to extend into September with above-normal rainfall. "Rainfall over all of India for the month of August is 268.1 mm, which is the seventh highest since 2001 and



the 45th rank since 1901. Rainfall over north-west India for the month of August is 265.0 mm, which is the highest since 2001 and the 13th rank since 1901. Rainfall over South India (250.6 mm), which is the third highest since 2001 and eighth highest since 1901," the IMD DG said in a press conference.

The IMD explained that the rapid revival of the monsoon from August 14 played a crucial role. "Active to vigorous monsoon conditions prevailed during the second half of August 2025 due to the formation of four low-pressure systems with a total of fifteen days," Mohapatra said.

RONALDO LAUNCHES UNREAL CALENDAR

September 2025: "Saudi, Welcome to Arabia" the consumer facing brand of the Saudi Tourism Authority (STA), launched its latest campaign starring Cristiano Ronaldo (CR7). Launching across key markets in Europe as well as India and China, "I Came for Football, I Stayed For More" brings to life a Saudi that offers visitors far more than the expected. Heralding the start of its extended season of high stakes sports, rousing entertainment, and breathtaking film, fashion and cultural events, the campaign harnesses TV, Social, Digital, and OTA to give audiences a taste of one of the world's most exciting destination calendars. Featuring football superstar and Saudi's most famous foreign resident, CR7, the film takes viewers on a journey through Saudi's cornerstone events. An awed CR7 sits in the stands - comparing the different sports to his own. Hushed monochromes give way to vibrant colour as we see more of what enticed CR7 to



stay in Saudi. From the adrenaline coursing through the crowd, we hear its roar - feeling the highs and lows of a shared experience. The emotion is palpable, and brings audiences into the thick of the action. This is Saudi - engaged, excited, and eager to take its place on the world stage.

The campaign highlights Saudi's diverse, year-round events held across Riyadh, Jeddah and AlUla, with curated packages making it ever easier to visit. As hosts of the FIFA World Cup 2034, AFC Asian Cup 2027, Esports Olympics Games 2027, Asian Winter Games

2029 among others, Saudi is bringing sport home. Its regular calendar includes largescale international events such as the Esports World Cup, Formula 1, LIV Golf Riyadh, Tennis, Saudi Pro League (RSL) - cementing its position as a hub for largescale events. From sports to culture and enter-

tainment, Saudi offers something for all interests. Its annual calendar continues to grow, with Riyadh Fashion Week, the Red Sea International Film Festival, Arts Biennales and the eponymous Seasons - held in Riyadh and Jeddah, forming the cornerstone of activities. From music to comedy, international and regional acts are taking the stage in Saudi, furthering reach and accessibility for ever more audiences. His Excellency Ahmed Al Khateeb, Minister of Tourism for Saudi, stated: "Today, Saudi is cementing its place as a global destination that combines cultural authenticity, warm hospitality, and the thrill of world-class events. In the tourism sector, we remain steadfast in our commitment to developing a seamless landscape that inspires the world and provides visitors with unforgettable experiences." Fahd Hamidaddin, CEO of the Saudi Tourism Authority, added: "This campaign with CR7 is a showcase of Saudi today.

Mr Ajay Piramal Unveils Anant's New Faculty and Graduate Housing



Ahmedabad, September 2025: Mr Ajay Piramal, President, Anant National University, inaugurated Anant's newest building, Faculty and Graduate Housing in the presence of key members of the university leadership. The event marks a significant milestone in the university's commitment to providing a vibrant living experience for the members of the Anant community. The newly built facility, designed by acclaimed Rushabh Parekh Design Studio (RPDS), has a built-up area of 26,475 sq m and comprises 172 apartments, including studio apartments and 1, 2 and 3 BHK homes. A true home-away-from-home crafted with care and attention to detail, the housing also features thoughtfully designed common spaces, a gymnasium, yoga room,

café and a visitor's lounge. Ensuring safety, the residence is equipped with CCTV surveillance across all common areas and is secured round the clock by Anant's dedicated security team. During the visit, Mr Piramal also interacted with the faculty and students, encouraging them to follow their passion and use their creativity to design solutions for global impact, something that Anant National University prepares them for. He said, "India is a young country, and you are the future. You can make a difference with your design thinking and develop solutions that are unique to India and globally relevant. Anant offers that opportunity and scope for you to create impactful solutions." Anant is currently undergoing a massive infrastructural transformation,

expanding over 1.5 lakh sq m to create a world-class learning environment. The state-of-the-art academic centres, equipped with cutting-edge technology, will ensure that students have access to the latest innovations in design and technology. What makes this expansion unique is the involvement of some of the world's most renowned architects, including BV Doshi/Rajeev Kathpalia, Bimal Patel, Rahul Mehrotra, Sasaki, Hafeez Contractor, Aniket Bhagwat and Vijay Arya. With this expansion, Anant National University reaffirms its commitment to providing world-class infrastructure to facilitate world-class learning, while also contributing to the mission of Viksit Bharat through design-driven innovation and excellence.

NATIONAL NUTRITION MONTH: HOW ALMONDS CAN ELEVATE YOUR DAILY NUTRITION

September 02nd 2025: A balanced diet is key to good health, and this year's Nutrition Month theme, "Food Connects Us Together," underscores the role of food in building connections. Starting the day with nutrient-dense foods like almonds, fruits, and whole grains fosters both energy and well-being. California Almonds, rich in 15 essential nutrients including zinc, magnesium, iron, and vitamin E, are a simple way to fuel mornings and support overall health. The Indian Council of Medical Research-National Institute of Nutrition (ICMR-NIN) also released Dietary Guidelines for Indians, which recognizes almonds as a nut to consume daily for good health. Eating almonds every day may support weight management, enhance heart health, and help control blood sugar levels. Bollywood actress Soha Ali Khan, known for her dedication to fitness, says, "I make it a point to follow healthy eating habits and encourage the same within my family. Being mindful of



our daily nutrition is essential for maintaining good health, so I consciously keep track of what we consume. I prefer starting my day with something light yet nourishing like California almonds, which keep me energized and satisfied for hours. Even when I'm on the go, I carry a small box of California almonds to snack

on. They not only help curb hunger but also contribute to my daily nutritional needs. This National Nutrition Month, I encourage everyone to start their day with nutritious foods like almonds and include them in your loved ones' diets as well." Commenting on National Nutrition Month, Ritika Samadder,

Regional Head of Dietetics at Max Healthcare, Delhi, said, "I urge people to take their health seriously and make conscious food choices. With rising junk food consumption, there has been a corresponding rise in health concerns across all age groups. It is therefore essential to include nourishing foods such as almonds in your daily diet as they help manage weight, cholesterol, and blood sugar, thereby supporting overall health. Being rich in Vitamin B2, Vitamin E, magnesium, and phosphorus, almonds also help keep you energetic throughout the day." Nutrition and Wellness Consultant Sheela Krishnaswamy said, "Our lifestyle and food choices are fueling health issues like diabetes, high blood pressure, and obesity. One simple yet often overlooked step is how we start our day, as it sets the tone for our energy and focus. Adding nutrient-rich foods like almonds, which include 15 essential nutrients, can make a real difference. The ICMR-NIN recommends regular nut consumption,

as it supports heart and gut health and helps manage diabetes and prediabetes. Beginning the day with almonds not only keeps you energetic but also helps meet the body's daily nutrient needs." Ayurveda expert Madhumita Krishnan said, "According to Ayurveda, meditation is an important way to start the day, but diet is equally vital as it reflects on our body, skin, and overall health. Almonds are considered a sattvic food, rich in vitamin E, healthy fats, and antioxidants that help nourish the skin from within. Siddha practice also recognizes almonds for their therapeutic role in addressing weakness from chronic and lifestyle-related conditions such as diabetes." National Nutrition Month serves as a reminder that every bite matters. This year, let's commit to acknowledging the crucial role of nutrition in overall well-being. By making mindful food choices and including nourishing options like almonds in our daily diet, we can stay energized, healthy, and reduce the risk of lifestyle diseases.

IN DOMESTIC DEMAND SET FOR A STRONG REVIVAL: PL CAPITAL

Mumbai 2025: PL Capital, one of India's most trusted financial services organizations, in its latest India Strategy Report titled "Ready for next leg of growth", highlighted that the conditions are ripe for a strong boost in domestic demand, driven by multiple tailwinds, that are likely to sustain beyond the festive season. Lower inflation (CPI at 1.6% with food deflation), normal monsoons boosting rural incomes, and a fiscal boost from ₹1,000 bn tax cuts in FY26 are laying the foundation for this recovery. The momentum is expected to strengthen further in 2H26 with the transmission of RBI's 100 bps rate cuts, lowering EMIs and stimulating demand for housing, automobiles, and personal loans. Complementing this, GST 2.0 reforms—which rationalize tax slabs and reduce prices across automobiles, durables, staples, and medicines—are poised to trigger broad-based consumption. The report emphasizes that



reviving consumption demand is critical to sustaining India's growth trajectory. Under the vision for 'Atamirbhar Bharat', with a focus on GST reforms, defence initiatives, support to agriculture, youth employment and energy security, the current US tariff challenge can be turned into a big opportunity. Indian markets have displayed notable resilience. The report highlights that Indian markets have displayed notable resilience, maintaining a largely flat trend since early July despite penal tariffs from the US and FII outflows of ₹410 bn. Corporate earnings have been reason-

able, with sales, EBITDA, and PAT broadly in line with expectations, deviating by just 2%, 0.9%, and -0.5% respectively. However, the fragile geopolitical environment and continued US tariff actions pose risks to global trade and GDP growth, as the full impact of higher import duties unfolds. NIFTY EPS estimates have been revised by -1.4%/-0.4% for FY26/27, though earnings are still projected to grow at a healthy 13.2% CAGR over FY25-27, with EPS expected at ₹1,254/1,445. At present, NIFTY trades at 18.9x one-year forward EPS, a marginal 1% discount to its 15/10-year average PE of 19.1x. Applying the 15-year average PE of 19.1x to March'27 EPS of ₹1,445, we derive a 12-month NIFTY target of 27,609 (versus 26,889 earlier at 18.6x FY27 EPS). Structural themes such as defence, infrastructure, EMS, hospitals, and power transmission remain intact, albeit with limited scope for further re-rating.

Sensex, Nifty open marginally higher ahead of key GST meet

Mumbai: The Indian benchmark indices opened marginally higher on Tuesday as investors are keen on the two-day GST Council meeting this week, where a major rate overhaul is expected. As of 9:26 am, the Sensex inched up 90 points or 0.11 per cent to 80,454, while the Nifty 50 moved 15 points up or 0.06 per cent to 24,640. The broadcap indices, Nifty Midcap 100 advanced by 0.31 per cent, and the Nifty Smallcap 100 inched up 0.10 per cent. Among sectoral indices, the Nifty media was the top gainer, rising 0.82 per cent, followed by Nifty Oil & Gas, which gained 0.34 per cent each. Nifty FMCG advanced 0.20 per cent. All other indices were in red, with Nifty IT losing 0.42 per cent. In the Nifty pack, top gainers included Eternal and Bajaj Finance, which gained 1.1 per cent and 0.7 per cent, respectively. Meanwhile, the top laggards were Asian Paints, Dr Reddys Labs, Hindalco, Maruti Suzuki and Axis Bank. Analysts noted that on the daily chart, Nifty formed

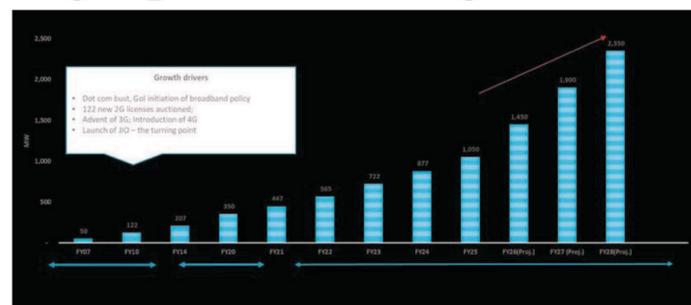


a morning star candlestick pattern, signalling a potential reversal. "The index is currently trading above its long-term EMA while approaching its short-term and medium-term EMAs. The immediate support is placed at 24,400, followed by 24,000. On the upside, resistance is seen at 24,700, followed by the 24,800-25,000 zone," said Mandar Bhojane from Choice Broking, Asia-Pacific markets traded mixed as investors assessed the Shanghai Cooperation Organisation (SCO) meeting of leaders in Tianjin, China, with tariff uncertainty weighing on sentiment. US

President Donald Trump reacted to the summit, calling trade ties with India "a totally one-sided disaster." China's Shanghai index slipped 0.59 per cent, and Shenzhen dipped 1.6 per cent. Japan's Nikkei was up 0.25 per cent, while Hong Kong's Hang Seng Index dipped 0.19 per cent. South Korea's Kospi inched up 0.72 per cent. The US markets were closed on Friday, as the Dow Jones Industrial Average slipped by 0.2 per cent, while the Nasdaq declined by 1.15 per cent and the S&P 500 lost 0.64 per cent.

"Infra-led growth outlook across sectors in India, remains strong despite geo-political challenges": CareEdge Ratings

Mumbai 2025: CareEdge Ratings in its latest sectoral outlook on India's infrastructure sector, the study evaluates opportunities, challenges, and investment potential across key segments including roads and highways, airports, ports, power, and renewable energy, while also focusing on emerging areas such as data centers and green hydrogen cited that the infrastructure investment continues to be a cornerstone of India's long-term economic growth, delivering a strong multiplier effect of nearly 2.5x on GDP. With government initiatives like Gati Shakti, the National Infrastructure Pipeline, and increasing private sector participation, the sector is poised to accelerate urbanization—expected to reach 42% of the population by 2030—while enabling sustainable energy transition and supporting India's broader development goals." Roads & Highways Sector: HAM-Monetisation Pipeline valued at nearly Rs. 2 lakh



crore by FY28 The roads and highways segment, traditionally one of the strongest pillars of India's infrastructure, is likely to face a temporary slowdown. The pace of execution of national highways is projected to decline by 7-10% in FY26 owing to reduced awarding activity and delays in obtaining approvals for Hybrid Annuity Model (HAM) projects. On the other hand, toll road traffic is expected to grow at a stable rate of around 7% in FY26, supported by strong domestic

coal production, multimodal logistics development, and the government's focus on creating industrial corridors. Importantly, the monetization outlook remains robust, with a pipeline of NH-HAM projects valued at nearly Rs. 2 lakh crore scheduled to be unlocked by FY28. However, challenges such as traffic diversion from greenfield expressways, increasing modal shift to rail, and regulatory uncertainties at the state level could weigh on the sector's growth trajectory. Airports

Sector: Passenger traffic is projected to expand at a compound annual growth rate (CAGR) of 7% between FY25 and FY27. The outlook for airports in India remains positive, albeit with some near-term moderation. Passenger traffic is projected to expand at a compound annual growth rate (CAGR) of 7% between FY25 and FY27. This is slightly lower than earlier estimates, largely due to delays in the induction of wide-bodied aircraft, heightened safety concerns, and geopolitical factors

affecting international travel patterns. Nonetheless, the long-term fundamentals of the sector remain intact. India continues to rank as the third-largest aviation market globally, behind only the United States and China, underscoring the structural demand potential that will continue to drive investments in capacity expansion and modernization of airport infrastructure. Ports Sector: Overall cargo traffic likely to grow by only around 2% year-on-year in FY26 India's port sector is expected to see muted growth in the near term, with overall cargo traffic likely to grow by only around 2% year-on-year in FY26. However, container cargo remains an exception, expected to register a much stronger growth of nearly 8% during the same period. Major ports continue to handle nearly 57% of total cargo volumes, maintaining their dominance in the sector. Growth drivers such as increased containerization, capacity additions.